04 - महाराष्ट्र हो या मिर्जापुर, कहानी सब जगह एक जैसी

05 - मध्य प्रदेश : प्रकृति के सफाई कर्मियों का 'स्वर्ग'

A Daily News Magacine
भोपाल
बुधवार, 05 मार्च, 2025

06 - खतरनाक स्थानों से हटाए गए होर्डिंग दोबारा लगे...

07 - जीएसआईटीएस में अगले वर्ष से बायोटेक्नोलॉजी के...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 177, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

हो के मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए
ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए
एक ही ठाँव पे ठहरेंगे तो थक जाएँगे
धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए
आप को ऊँचे जो उठना है तो आँसू की तरह
दिल से आँखों की तरफ़ हँस के उछलते रहिए
शाम को गिरता है तो सुब्ह सँभल जाता है
आप सूरज की तरह गिर के सँभलते रहिए
प्यार से अच्छा नहीं कोई भी साँचा ऐ 'कुँवर'
मोम बन के इसी साँचे में पिघलते रहिए।

– कुंवर बेचैन

प्रसंगवश

क्या ट्रंप भारत को पुराने हथियार बेचने की पेशकश कर रहे हैं?

ले.जन. एच.एस. पनाग (रिटा.)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान के अनुसार भारत-अमेरिका के भावी संबंध के जो तीन मूल आधार हो सकते हैं उनमें से एक आधार होगा सैन्य संबंध। हाल में 'कम्पेक्ट' (सैन्य सहयोग के लिए अवसरों, व्यापार तथा टेक्नोलॉजी में वृद्धि की कोशिश) नामक जो नई रणनीतिक पहल की गई है वह इसी तथ्य को रेखांकित करती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप सैन्य सहयोग को आकर्षक व्यापारिक लेन-देन के अवसर के रूप में देख रहे हैं।

संयुक्त प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा कि 'इस साल से भारत को सैन्य सामग्री की हमारी बिक्री में अरबों डॉलर की वृद्धि की जाएगी। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने 'भारत द्वारा अमेरिका से ज्यादा-से-ज्यादा सैन्य साजोसामान हासिल करने के महत्व' पर ज़ोर दिया था। भारत ने एफ-35 की मांग कभी नहीं की क्योंकि यह महंगा भी है और इसकी संचालन लागत भी बहुत ऊंची है। ट्रंप के निजी सलाहकार एलन मस्क ने इसे बनाने वालों को मूर्ख तक कहा था, क्योंकि अब ड्रोन टेक्नोलॉजी तेजी से उभर रही है।

अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग से भारत की अपेक्षाएं बिल्कुल अलग हैं, जो कि मोदी के इस बयान से जाहिर होता है कि 'अमेरिका भारत की रक्षा तैयारियों में अहम भूमिका निभाता है। एक रणनीतिक तथा भरोसेमंद सहयोगियों के रूप में हम रक्षा सामग्री के संयुक्त विकास, उत्पादन और टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की ओर सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं।' यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी सबसे अहम मसले को भूल गए– भविष्य की सैन्य टेक्नोलॉजी के संयुक्त रूप से विकास और साझीदारी के मसले को।

एक गतिशील बहुआयामी रक्षा सहयोग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए ट्रंप और मोदी ने घोषणा की थी कि 2025 में वे '21वीं सदी में भारत-अमेरिका की बड़ी रक्षा साझीदारी के फ्रेमवर्क' पर दस्तखत करने की योजना बना रहे हैं। इस बात पर सहमति बनी कि अमेरिका भारत को रक्षा सामग्री की बिक्री बढ़ाएगा और भारत के साथ मिलकर उनका उत्पादन करेगा ताकि दोनों मिलकर काम कर सकें और रक्षा उद्योग में आपसी सहयोग मजबूत हो। भारत की रक्षा संबंधी जरूरतों को तेजी से पूरा करने के लिए दोनों नेताओं ने साल 2025 के दौरान नई खरीदों, और जेवलीन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) और स्ट्राइकर इन्फैन्ट्री कंबैट वेहिकल्स (आइसीवी) का भारत में उत्पादन करने की योजनाओं की घोषणा की। उन्हें यह भी उम्मीद है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए छह और पी-81 मेरीटाइम पैट्रोल विमान हासिल किए जा सकेंगे। हालांकि संयुक्त बयान में इसका विशेष तौर पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन भारत अपने एलसीए मार्क-2 के लिए जीई-414 जेट इंजिन भी हासिल करना चाहता है। यह इंजिन इसके फ़िफ्थ जेनरेशन एडवांस्ड मीडियम कंबैट विमान (एएमसीए) प्रोग्राम को भी ताकत देगा और देसी एयरो इंजिन के विकास का रास्ता भी साफ करेगा।

दोनों देशों ने हथियार हस्तांतरण के अपने नियमों की भी समीक्षा करने पर भी सहमति दी है। इसमें अमेरिका का 'इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस (आईटीएआर)' भी शामिल है। इस समीक्षा का उद्देश्य होगाः रक्षा व्यापार को व्यवस्थित करना, टेक्नोलॉजी का आदान-प्रदान, कल-पुर्जों की सप्लाई, और अमेरिका से उपलब्ध सैन्य साजोसामान की देश के अंदर ही मरम्मत आदि। दोनों देशों की खरीद व्यवस्थाओं में तालमेल के लिए एक 'रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट' समझौता करने पर भी वार्ता की जाएगी।

दोनों देशों ने अंतरिक्ष, हवाई सुरक्षा, मिसाइल, समुद्री और समुद्र के अंदर के साजोसामान से संबंधित टेक्नोलॉजी के मामले में डिफेंस टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति बनाई। अमेरिका भारत को फ़िफ्थ जेनरेशन फाइटर विमान और समुद्र के अंदर के सैन्य साजोसामान उपलब्ध कराने की अपनी नीति की समीक्षा करेगा। स्वचालित हथियारों के बढ़ते महत्व के मद्देनजर 'ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस' नामक एक नयी पहल की घोषणा की गई जिससे उद्योग तथा उत्पादन के क्षेत्र में साझीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र से संबंधित इस संयुक्त बयान में सभी उचित मुद्दों को छुआ गया है। लेकिन भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के पिछले दो दशकों में वादे तो बहुत किए गए लेकिन उनसे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। यहां तक कि प्रस्तावित 'टेन इयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट' भी कोई नया नहीं है। अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग करने के पीछे भारत के दो उद्देश्य हैं। पहला अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए दोनों सरकारों के बीच करारों के जरिए अत्याधुनिक वेपन सिस्टम्स की खरीद करना। दूसरा,आपसी सहयोग से सिस्टम्स के विकास तथा उत्पादन के जरिए भावी सैन्य टेक्नोलॉजी हासिल करना। दोनों मामलों में टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत किया जाना था, जिसमें कुछ 'वन टाइम' करारों की छूट शामिल थी। अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना भारत का मूल राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत रहा है। इसलिए वह अमेरिका के साथ औपचारिक रूप से जुड़ना नहीं चाहता था। भारत जब ग्लोबल टेंडर के जरिए सैन्य साजोसामान हासिल करना चाहता है तब अमेरिका उसमें किसी तरह की बोली नहीं लगाता। इसकी जगह वह भारत की जरूरतों का आकलन करता है और समय-समय पर द्विपक्षीय वार्ताओं में पेशकश किया करता है। कभी-कभी भारत भी अपनी दिलचस्पी जाहिर किया करता है। भारत ने उससे 20 अरब डॉलर मूल्य के सैन्य साजोसामान खरीदे हैं। लेकिन आपसी सहयोग से वेपन सिस्टम के विकास तथा उत्पादन की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने जो वेपन सिस्टम हासिल किए हैं और जो अभी उत्पादन प्रक्रिया में हैं उनमें से अधिकतर पुरानी पड़ चुकी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। उन्हें पिछले तीन दशकों में विकसित किया गया। ट्रंप अपने दूसरे अवतार में सौदेबाजी और 'मागा' (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) पर ज़ोर दे रहे हैं। वे अमेरिका, चीन और रूस की त्रिमूर्ति के वर्चस्व पर आधारित नयी विश्व व्यवस्था को आकार देने में जुटे हैं। भारत-अमेरिका सहयोग को वे अल्पकालिक और व्यापार आधारित महत्व देते हैं, जिसमें भारत को चीन से लड़ने में सैन्य रूप से सक्षम बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। ट्रंप का यह कार्यकाल अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण और भारत के प्रति अमेरिकी विदेश नीति तथा संबंधों को किस तरह प्रभावित करेगा, इस पर अभी कोई फैसला देना जल्दबाज़ी होगी। मेरे विचार से भारत को इस आंधी और उथलपुथल को शांत होने तक इंतजार करना चाहिए, खासकर रक्षा मामलों के लिहाज से। भारत को रक्षा मामलों, खासकर भविष्य की 'असीमेट्रिकल टेक्नोलॉजी' के मामले में आत्मनिर्भरता की टेक पर कायम रहना चाहिए।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

बिजनेस सरल बनाने के लिए 40 हजार अनुपालन हटाए

● मोदी बोले-अब जन विश्वास बिल 2.0 पर कर रहे काम ● पीएम ने पोस्ट बजट वेबिनार कार्यक्रम को किया संबोधित

नई दिल्ली (एजेंसी)। किसी भी देश के विकास के लिए स्थिर नीतियां और अच्छा कारोबारी माहौल महत्वपूर्ण है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करते हुए 40,000 से अधिक अनुपालन हटा दिए गए। एक सरलीकृत आयकर प्रणाली भी शुरू की है।

अब हम जन विश्वास बिल 2.0 पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। ये बजट, हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट की सबसे खास बात रही, अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी।

कई सेक्टर्स ऐसे हैं, जहां एक्सपर्ट्स ने भी जितनी अपेक्षाएं की थीं, उससे अधिक कदम सरकार ने उठाए। आज दुनिया का हर देश, भारत के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस पार्टनरशिप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ, इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली।

14 सेक्टर्स को इस योजना का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 7.5 करोड़ यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है, 13 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है।

महाकाल मंदिर में 488 होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिक होंगे तैनात

मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी, दूसरे अनुपूरक बजट को भी मिली स्वीकृति

भोपाल। प्रदेश में अब कोई भी शासकीय विभाग प्लानिंग एरिया के बाहर भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकेगा और राज्य सरकार को प्रस्ताव देगा, जिसे सरकार परमिशन देगी। ऐसे प्रोजेक्ट की कम से कम लागत 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मोहन सरकार ने नगर और ग्राम निवेश से संबंधित विधेयक को भी मंजूरी दे दी है, जिसे विधानसभा में लाया जाएगा। इसके साथ, ही महाकाल मंदिर में 488 होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती के लिए भी कैबिनेट ने सहमति दी है। इसके अलावा, दूसरे अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को समिट के प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए सतत फॉलो-अप करने और विभाग प्रमुखों के साथ रिव्यू करने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव हर हफ्ते रिव्यू करेंगे और मुख्य सचिव को इसकी रिपोर्ट देंगे। मंत्री भी इन प्रस्तावों को साकार करने के लिए कार्य करेंगे। इस दौरान सेक्टरवार मिले निवेश प्रस्तावों की जानकारी साझा की गई। इस साल 30 मार्च से 30 जून तक प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जाएगा।

प्लानिंग एरिया के बाहर भी प्रोजेक्ट तय कर सकेंगी निर्माण एजेंसियां- आज कैबिनेट बैठक में नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक के तहत कोई भी शासकीय विभाग प्लानिंग एरिया के बाहर भी निवेश कर सकेगा और राज्य सरकार को प्रस्ताव देगा, जिसे सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी। एमपीआईडीसी, एमपीआरडीसी, साडा, विकास प्राधिकरण सहित अन्य एजेंसियों को 500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट तैयार करने पर इस प्रकार की छूट दी जाएगी। उज्जैन जिले में महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 488 अतिरिक्त होमगार्ड स्वयंसेवकों के पद सृजित किए गए।

बच्चों को संस्कार देने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी ट्रेनिंग

भारत सरकार के सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत 'पोषण भी, पढ़ाई भी' कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि वे बच्चों को सामान्य ज्ञान के साथ-साथ संस्कार भी दे सकें।

कैबिनेट बैठक में कुछ सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों के राज्य से बाहर कराए गए इलाज पर खर्च की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। जनजातीय कार्य विभाग की सहायक शिक्षक अधीक्षक (जिला रीवा)- 3.30 लाख रुपए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मिठूलाल चर्मकार (पशु परिचारक, जिला अनूपपुर) अमित जोटे (सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, बैतूल) ईश्वरदास चंदेलकर (रिटायर्ड उप वन क्षेत्रपाल)- उनकी पत्नी अंजली चंदेलकर का इलाज गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में कराने पर 2.27 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति पर विचार किया गया। भगवानदीन पांडेय (सहायक शिक्षक, हटवा खास, जिला सीधी)।

केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़छाड़ मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार

● 3 की तलाश जारी, आदित्य ठाकरे बोले-महिला पर अत्याचार करने वालों को फांसी दो

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, 3 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। जलगांव एसपी महेश्वर रेड्डी के मुताबिक, छेड़छाड़ मामले में 2 मार्च को मुक्ताईनगर पुलिस स्टेशन में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम अनिकेत भोई, किरण माली, अनुज पाटिल है। आरोपी अनिकेत का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। चौथा आरोपी नाबालिग है। महेश्वर रेड्डी ने कहा- 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

रोड एक्सीडेंट में घायलों को फ्री इलाज इसी महीने से

नई दिल्ली (एजेंसी)। रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने यानी मार्च 2025 से डेढ़ लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। यह नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा। देशभर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। एनएचएआई इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, योजना के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले ही संशोधन हो चुका है। इस योजना को पूरी तरह से लागू करने से पहले बीते 5 महीनों में पुड्डुचेरी, असम, हरियाणा और पंजाब सहित छह राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जो सफल रहा। ऑफीसर ने बताया कि घायल को पुलिस या कोई आम नागरिक या संस्था जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाएगी, उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस भी जमा नहीं करनी होगी। घायलों के साथ चाहे परिजन हो या नहीं, हॉस्पिटल उसकी देखरेख करेंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही हॉस्पिटल को कैशलेस इलाज देना होगा। नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लॉन्च की थी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को रोड एक्सीडेंट पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कैशलेस ट्रीटमेंट योजना शुरू किया था। इसके बाद 7 जनवरी 2025 को गडकरी ने योजना को देशभर में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की। इससे देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी।

● चमोली हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

जोशीमठ के जिलाधिकारी को बनाया गया है जांच अधिकारी

देहरादून (एजेंसी)। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने 28 फरवरी को माणा में हुए हिमस्खलन हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जोशीमठ के डीएम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई थी। माणा के पास हाल ही में भारी हिमस्खलन हुआ था, जिसके चपेट में बीआरओ के 54 श्रमिक आ गए थे। बीआरओ के शिविर पर हुए इस हादसे में 8 मजदूरों की जान गई थी। आईटीबीपी और सेना के जवानों ने जब रेस्क्यू अभियान शुरू किया तब

पहले दिन 33 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला गया था। दूसरे दिन रेस्क्यू अभियान में एनडीआरएफ भी शामिल हुई। रेस्क्यू टीमों ने 46 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया था जबकि चार श्रमिकों के शव बरामद हुए थे।

उज्जैन में विक्रमोत्सव

अनुप्रिया देवताले के वायलिन की स्वर लहरियों ने की माधुर्य वर्षा

महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 का भव्य और अनूठा आयोजन प्रतिदिन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 125 दिवसीय विक्रमोत्सव का शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक दीर्घकालीन आयोजन में निरंतर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की श्रृंखला जारी है। इसी क्रम में पं. सूर्यनारायण व्यास संकुल, कालिदास अकादमी में ख्याति प्राप्त कलाकार अनुप्रिया देवताले ने वायलिन वादन की कर्णप्रिय प्रस्तुति से श्रोताओं की दाद हासिल की।

उज्जैन से डॉ. जफर महमूद

इंदौर में जन्मी अनुप्रिया देवताले ने संगीत की शिक्षा प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां और प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित रामनारायण जी से हासिल की है। विश्वप्रसिद्ध वरिष्ठ कलाकारों के साथ गुरु शिष्य परंपरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर अनुप्रिया ने शास्त्रीय वायलिन वादन में अपनी मौलिक पहचान बनायी है। अनुप्रिया देवताले हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपनी उत्कृष्टता के लिए जानी जाती हैं। उनका वादन सौम्यता, तकनीकी निपुणता और गहरी अभिव्यक्ति से भरपूर है। भावनात्मकता और माधुर्यमय मौलिक शैली की धनी अनुप्रिया देवताले दुनियाभर के 40 देशों में प्रस्तुति दे चुकी हैं।

विक्रमोत्सव में अनुप्रिया ने अपने वायलिन वादन में राग भीमपलासी पर आधारित तीन रचनाएं प्रस्तुत कीं। विलंबित रचना झप ताल में तथा मध्य लय और दूर्त लय तीन ताल में प्रस्तुत करते हुए उनका वादन उत्कृष्ट पर पहुंचा। राग भीमपलासी एक मधुर, शांति देने वाला और भावपूर्ण राग है। उन्होंने राग भीमपलासी की सूक्ष्मताओं को वायलिन पर बड़ी सुंदरता से प्रकट किया। गायकी अंग की शैली में उनका वायलिन वादन नवाचार और परंपरा का सुंदर संतुलन प्रस्तुत करता रहा।

उनके वादन में केवल तकनीकी दक्षता ही नहीं, बल्कि राग की गहरी संवेदनशीलता को अपने में समाहित किए हुए था। उनके साथ तबले पर गांधार राजहंस और तानपुरे पर रश्मि ने संगत की। कार्यक्रम के आरंभ में विक्रमोत्सव के पुराविद् डॉ. रमण सोलंकी, प्रो. प्रशांत पुराणिक एवं कवि दिनेश दिग्गज ने अनुप्रिया देवताले का गुलदस्ता पैश कर स्वागत किया।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 22 °c | न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार,05 मार्च 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

रियायत | अब सलाखों से बाहर निकलकर कमाएंगे पैसा, अच्छे आचरण का मिलेगा ईनाम

यूपी में जेल में बंद कैदियों के लिए नई पहल

गोरखपुर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। जेल प्रशासन की पहल पर अब उन्हें कैद से बाहर निकाला जाएगा और उनसे रोजगार कराकर आचरण में सुधार और पुनर्वास का का मौका दिया जाएगा। जल प्रशासन के प्रयास की लोक प्रशंसा कर रहे हैं। गोरखपुर जेल प्रशासन द्वारा नई पहल करते हुए सजायाफ्ता कैदियों के लिए एक नई योजना तैयार की है, इसके तहत अच्छे आचरण और अनुशासित कैदियों को

जेल की चारदीवारी से बाहर निकाल कर रोजगार कराया जाएगा। इसके लिए जेल प्रशासन की तरफ से दो पेट्रोल पंप खोले जा रहे हैं। इन पेट्रोल पंपों पर यह कैदी काम करेंगे, इनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरा से कराई जाएगी और फिर शाम को उन्हें वापस जेल पहुंचा दिया जाएगा। कैदियों के सामाजिक आचार विचार और व्यवहार की मॉनिटरिंग की जाएगी और फिर उन्हें इसका इनाम भी दिया जाएगा।

इस बारे में जेल अधीक्षक दिलीप पांडेय ने बताया कि कैदियों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है, सजायाफ्ता अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा खोले जा रहा है तीन पेट्रोल पंपों पर रोजगार दिया जाएगा। इसकी लिस्ट शासन को भेजी गई है। इस बात की मंजूरी मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस निर्णय का फायदा लंबे समय से सजा काट रहे कैदियों को अवसाद से बाहर निकालने में मिलेगा। ताकि सामाजिक परिवेश में फिर से इन्हें ढाला जा सके और इनके जीवन में सुधार लाया जा सके। इस तरह की पहल विदेशो में पहले से चल रही है। जहां कैदियों को जेल से बाहर निकाल कर रोजगार कराया जाता है। यहां जिला कारागार में भी होने वाली खेती में कैदी काम करते थे, लेकिन अब इन्हें बाहर भी निकाला जाएगा।

औरंगजेब की तारीफ पर महाराष्ट्र में बरपा हंगामा

सपा विधायक अबू आजमी पर भड़के नेता, सस्पेंड करने की डिमांड

मुंबई (एजेंसी)। सपा विधायक अबू आजमी की ओर से मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने पर महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को हंगामा मच गया। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब का शासन इतना अच्छा था कि उसके दौर में भारत सोने की चिड़िया था। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक ने दावा किया था, 'हमारा जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दुनिया का 24 प्रतिशत था और भारत को (औरंगजेब के शासनकाल के दौरान) सोने की चिड़िया कहा जाता था।' महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन 'महायुति' के सदस्यों ने मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने के लिए मंगलवार को सपा के विधायक अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने की मांग की। इस मुद्दे पर हंगामा इतना बरपा कि कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों ने दावा किया कि आजमी औरंगजेब के वंशज हैं।

पाकिस्तानी युवती के जाल में फंसा रेलवे का कर्मचारी

● देश के खिलाफ करने लगा जासूसी, अब फंसा शिकंजे में

जयपुर (एजेंसी)। बीकानेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले रेलवे कर्मचारी को राजस्थान इंटेलिजेंस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भवानी सिंह को पाकिस्तानी युवती ने हनीट्रैप में फंसाया। रेलवे कर्मचारी पैसों के लालच में सोशल मीडिया के जरिए महिला एजेंट से संपर्क में रहा। वह सेना की गतिविधियों की गोपनीय जानकारी दे रहा था। इसके बदले भवानी

सिंह आईएसआई से पैसा ले रहा था। इंटेलीजेंस अधिकारियों ने बताया- पाकिस्तानी एजेंसियों की ओर से राज्य में की जाने वाली जासूसी गतिविधियों पर निगरानी के दौरान इस कॉल को ट्रेस किया था। इसके बाद इंटेलीजेंस की टीम आरोपी भवानी सिंह तक पहुंची। जो रेलवे में पॉइंटमैन के पद पर काम कर रहा था। रेलवे कर्मचारी कई महीनों से निमी नाम की पाकिस्तानी युवती के संपर्क में था।

यूजीसी ने तैयार किया ड्राफ्ट, आप भी दे सकते हैं सुझाव

कॉलेजों में अब रुकेगा जाति के आधार पर भेदभाव!

● सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मजबूत और प्रभावी तंत्र है बनाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन (यूजीसी) ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जाति के आधार पर भेदभाव और अन्य संबंधित समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए एक मजबूत और प्रभावी तंत्र बनाना चाहता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि यूजीसी ने कुछ चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मसौदा नियम तैयार किए हैं। ये सुझावों के लिए प्रकाशित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता, हस्तक्षेपकर्ता या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव यूजीसी को भेज सकते हैं। उन्हें उचित रूप से विचार में लिया जाएगा।

जवाब नहीं दिया तो रद्द हो सकती है मान्यता!- कोर्ट ने पहले यूजीसी को केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों से समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना और शिकायतों के आंकड़े एकत्र करने को कहा था। सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने बताया कि 40 फीसदी विश्वविद्यालयों और 80 फीसदी कॉलेजों ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। इस पर

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई संस्थान जवाब नहीं देता, तो इसे यह समझा जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यूजीसी को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं, जिसमें किसी संस्थान की संबद्धता रद्द करने की शक्ति भी शामिल हो, तो यह प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई मई 2025 में तय की है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की ओर से दाखिल याचिका पर यह निर्देश दिए थे।

बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार

खट्टर ने दिया नया नारा, कहा-नीतिश के नेतृत्व में बनाएंगे सरकार

दिलीप जायसवाल बने बिहार भाजपा अध्यक्ष, छोड़ा था मंत्री का पद

पटना (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को भाजपा के कार्यक्रम में ऐलान किया कि नीतिश कुमार के नेतृत्व में 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। पटना के बापू सभागार में आयोजित प्रदेश परिषद की बैठक में उन्होंने नारा दिया- बिहार है तैयार फिर से एनडीए सरकार। बैठक में बीजेपी के

प्रदेश अध्यक्ष पद पर दिलीप जायसवाल के नाम की घोषणा की गई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, नीतिश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनवाए। जातिवाद से ऊपर उठ कर काम करना है। मोदी जी ने जाति से ऊपर उठकर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। शहरी विकास और पावर डिपार्टमेंट मेरे पास है, बिहार की जो जरूरत है बताइए, हम मदद करेंगे। मंत्री जीवेश मिश्रा को भी बोल दिया हूं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, अगले 6 महीने में सभी कार्यकर्ता सभी सीट को भाजपा की सीट समझकर जिताएं।

सचिन को नाखूनों से नोचा...

● जान बचाने के लिए खूब लड़ी थी कांग्रेस नेत्री ● हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस का खुलासा

चंडीगढ़ (एजेंसी)। कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सचिन ने मोबाइल फोन के चार्जर की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए हिमानी ने खूब संघर्ष किया था। इस दौरान हिमानी के नाखून लगने से सचिन के हाथों पर भी चोटें आई थी। इससे सचिन का खून निकल आया था। सचिन का खून वहां पड़ी रजाई पर लग गया था। इस कारण सचिन ने रजाई का कवर उतारकर उसे भी सूटकेस में शव के साथ ही पैक कर दिया था। इसके बाद वो हिमानी की स्कूटी लेकर कानौन्दा स्थित अपनी दुकान पर चला गया। साथ में वह हिमानी की अंगूठियां, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप व अन्य आभूषण एक बैग में लेकर गया। फिर दोबारा आकर हत्या की।

बुलडोजर एक्शन पर फंस गई भगवंत मान सरकार

● अपराधियों के खिलाफ कर रही थी कार्रवाई, एचसी ने मांगा जवाब

चंडीगढ़ (एजेंसी)। नशा तस्करों की संपत्तियों पर बुलडोजर ऐक्शन को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार फंसती नजर आ रही है। पीपल वेलफेयर सोसायटी द्वारा दायर याचिका को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मान सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार, पंजाब परिवहन विभाग के सचिव, लुधियाना पुलिस कमिश्नर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़ के

जोनल डायरेक्टर को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस मामले में क्या प्रभाव है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह निर्णय किसी भी आरोपी के खिलाफ बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए संपत्ति को ध्वस्त करने पर रोक लगाता है, जिसे पंजाब पुलिस को भी मानना चाहिए। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को तय की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति जब्त करने के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई है।

सरपंच हत्याकांड की बलि चढ़ गए मंत्री धनंजय मुंडे

महाराष्ट्र के मंत्री पद से देना पड़ा इस्तीफा, था भारी दबाव

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के बीड में सरपंच हत्या मामले में एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक और मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा सौंप दिया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे से इस्तीफा मांगा था। उन्होंने इसके लिए एनसीपी प्रमुख अजित पवार और पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल से भी बातचीत की थी। मुंडे महाराष्ट्र सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री थे। आरोप है कि बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में मुंडे के करीबी वाल्मीक कराड का हाथ है। एटीएस ने कराड को हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। हत्या से जुड़ी तस्वीरें अब सामने आई हैं।

अयोध्या साजिश

अब्दुल के लिंक तलाश रही एटीएस, 8 शहरों में छापा

आतंकी संगठन ने ब्रेनवॉश किया, कहा-अयोध्या में तुम पर जुल्म हुआ, अब बदला लो

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या के अब्दुल रहमान की गिरफ्तार के बाद एटीएस ने छापेमारी शुरू कर दी है। 8 शहरों में संदिग्धों के घरों को खंगाला जा रहा है। उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई अब्दुल रहमान से मिले इनपुट के आधार पर की जा रही है। एटीएस की टीम ने मंगलवार सुबह 4 बजे से अयोध्या, गोंडा, आजमगढ़, मऊ, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर और बलिया में डेरा डाल रखा है। यहां संदिग्धों की तलाश कर रही है। वहीं बलिया के सुखपुरा थाने के

बुडिया गांव में कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। आतंकी संगठन ने अब्दुल का ब्रेनवॉश किया। वीडियो भेजकर कहा- अयोध्या में तुम लोगों पर जुल्म हुआ है। अब तुम लोगों को इस जुल्म का बदला लेना है। अब्दुल के मोबाइल से ऐसे वीडियो मिले हैं। पुलिस के मुताबिक वह जिस आतंकी संगठन के ग्रुप से जुड़ा था, उस पर लगातार मैसेज आ रहे थे कि अयोध्या में तुम्हारे साथ गलत हुआ...अब बदला लेने का वक्त आया है। 2 मार्च को केंद्रीय एजेंसी के इनपुट के आधार पर फरीदाबाद के सोहना रोड स्थित पाली इलाके में रविवार रात एक खंडहरनुमा मकान से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी की गई थी। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। गुजरात एटीएस ने पाली इलाके से गिरफ्तार किया था।

अमेरिकी टैरिफ पर चीन और कनाडा की जवाबी कार्रवाई

● मैक्सिको ने भी बना लिए प्लान, टैरिफ के खिलाफ उठाएगा कदम

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ घोषित किए गए टैरिफ मंगलवार से लागू हो गए हैं। इससे दुनियाभर में ट्रेड वॉर की आशंका पैदा हो गई है। ट्रंप प्रशासन की योजना के अनुसार, अमेरिका के लिए सभी मैक्सिकन निर्यातों पर 25 प्रतिशत का

शुल्क लगेगा, अधिकांश कनाडाई निर्यातों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगेगा, जबकि ऊर्जा उत्पादों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगेगा। वाइट हाउस की ओर से जारी एक कार्यकारी आदेश के अनुसार, पिछले महीने चीन पर लगाए गए 10 प्रतिशत शुल्क को दोगुना करके 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा। 4 फरवरी को ट्रंप ने चीन पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। तीनों देशों ने अमेरिकी टैरिफ पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और जवाबी उपायों का वादा किया है, जो न केवल तीनों के बीच तनाव बढ़ा सकता है।

मिस नूतन -2025 के अंतर्गत पारंपरिक परिधान दिवस

भोपाल। सरोजिनी नायडू महाविद्यालय में पारंपरिक परिधान दिवस का आयोजन, 03 मार्च 2025 को पूर्ण भव्यता एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह उद्घाटन के साथ ही पहले दिन को "Traditional Attire Day" के रूप में मिस नूतन प्रतियोगिता के अंतर्गत मनाया गया, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध परंपराओं के उत्सव को छात्राओं द्वारा मोहक अंदाज़ में मंच पर प्रस्तुत किया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्राओं को भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना और उनमें अपनी परंपराओं के प्रति गर्व की भावना विकसित करना था।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यह आयोजन न केवल हमारी विरासत

(Heritage) और पहचान (Identity) को सहेजने का अवसर है, बल्कि हमें विभिन्न संस्कृतियों को जानने, समझने और सम्मान देने की प्रेरणा भी देता है। प्राचार्य डॉ दीप्ति श्रीवास्तव द्वारा छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि

'मिस नूतन 2025' के इस परिधान दिवस ने "Unity in Diversity" की भावना को और प्रबल किया, जहां 22 छात्राओं ने भारतीय परंपराओं का सम्मान किया और भारत के विभिन्न राज्यों की पहचान प्रदर्शित करते हुए उस राज्य की परिधान के साथ समृद्ध संस्कृति का गर्व से प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महाविद्यालय की सभी छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, कार्यक्रम की प्रभारी डॉ अर्चना गौड़ द्वारा यह बताया गया कि यह आयोजन एक यादगार अनुभव बन गया और छात्राओं को उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व निखारने का सुअवसर प्रदान करता है।

'सुप्रीम' फैसला, एमपी में दृष्टिबाधित भी बन सकेंगे जज

कोर्ट ने कहा-दिव्यांगता के आधार पर न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब दृष्टिबाधित दिव्यांग भी अदालतों में जज बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिबाधित दिव्यांगों को न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दिए एक फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा नियमों के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया, जिसमें नेत्रहीन और कमजोर दृष्टि वाले उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा से बाहर रखा गया था। अदालत ने कहा कि, नेत्रहीन और कमजोर दृष्टि वाले उम्मीदवार न्यायिक सेवा की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण और सहायक सुविधाएं देकर दिव्यांग उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा में समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने यह फैसला एक स्वत : संज्ञान मामले में दिया है। जिसमें मध्यप्रदेश सेवा

परीक्षा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 6 ए को चुनौती दी गई थी। अदालत ने नियम 7 के उस प्रावधान को भी खारिज कर दिया, जो दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की प्रैक्टिस या 70 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को निर्धारित करता था। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि, यह नियम शैक्षिक योग्यता और न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता के लिए लागू रहेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि ये अंक पहले प्रयास में ही प्राप्त किए गए हों या उम्मीदवार के पास तीन वर्षों का अनुभव हो।

अदालत ने कहा- भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव नहीं होना चाहिए- अदालत ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों से न्यायिक सेवा में भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य को उनके लिए एक समावेशी ढांचा बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि, ऐसा कोई भी परोक्ष भेदभाव जो दिव्यांग व्यक्तियों को बाहर करने का कारण बने, चाहे वह कट-ऑफ अंक के माध्यम से हो या प्रक्रियागत बाधाओं के रूप में हो उसे रोका जाना चाहिए ताकि वास्तविक समानता को बनाए रखा जा सके।

न्यायिक सेवा भर्ती में दिव्यांग उम्मीदवारों का हक- कोर्ट ने कहा है कि, जो दिव्यांग उम्मीदवार पहले से चयन प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं। वे अब इस फैसले के आधार पर न्यायिक सेवा के लिए योग्य माने जाएंगे और यदि वे अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्ति मिल सकती है। यह मामला 3 दिसंबर 2024 को विचाराधीन रखा गया था, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस भी होता है। अदालत ने राजस्थान न्यायिक सेवा में आवेदन करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों की याचिकाओं पर भी विचार किया और कहा कि, वे अगले भर्ती चक्र में भाग लेने के लिए पात्र होंगे यदि वे आवेदन करते हैं। इस मामले की सुनवाई का आधार तब बना, जब एक नेत्रहीन उम्मीदवार की मां ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र भेजा। इसमें उनके बेटे को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने की शिकायत थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका में परिवर्तित किया और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सचिव, मध्यप्रदेश सरकार और भारत सरकार को नोटिस जारी किया।

मोहन सरकार ने फिर लिया 6 हजार करोड़ का कर्ज

● इस साल अब तक 47 हजार करोड़ रुपए ले चुकी मप्र सरकार

भोपाल। मोहन यादव सरकार मंगलवार को फिर बाजार से छह हजार करोड़ रुपए के तीन कर्ज ले रही है। इसका भुगतान सरकार को बुधवार को होगा। दो-दो हजार करोड़ रुपए के यह कर्ज 14 साल, 20 साल और 23 साल की अवधि के हैं। सरकार इसके ब्याज का भी भुगतान करेगी। इसके साथ ही मोहन सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक 47 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इसके पहले 20 फरवरी को भी 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। चालू वित्त वर्ष में सरकार पिछले वित्त वर्ष से साढ़े चार हजार करोड़ का अधिक कर्ज ले चुकी है। अभी आने वाले पच्चीस दिनों में कुछ और कर्ज सरकार ले सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दस दिन बाद विधानसभा के बजट सत्र के पहले मोहन यादव सरकार ने फिर छह

हजार करोड़ के कर्ज के लिए नोटिफिकेशन किया है। कर्ज की यह राशि मंगलवार को आक्शन की गई है। आज जो कर्ज बाजार से लिया गया है वह केंद्र सरकार द्वारा तय लिक्विडिटी लिमिट के भीतर बताया जा रहा है।

जीआईएस से पहले लिया था छह हजार करोड़ का कर्ज- पिछले माह 24 और 25 फरवरी को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पहले मोहन सरकार ने 20 फरवरी को 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। तीन अलग-अलग कर्ज 12 साल, 15 साल और 23 साल की अवधि के लिए लिया गया। इस कर्ज के बाद प्रदेश सरकार का चालू वित्त वर्ष में लिया गया कुल कर्ज 41 हजार करोड़ रुपए हो गया था। इसके पहले वर्ष 2025 के पहले दिन एक जनवरी को सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। मध्यप्रदेश की जनता पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी।

शारदा विहार आवासीय विद्यालय में पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का शुभारंभ

विश्व भारत की ओर देख रहा है उसे मानवता की दिशा देनी होगी : डॉ. मोहनराव भागवत

भोपाल। विद्या भारती द्वारा आयोजित पांच दिवसीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग 2025 का शुभारंभ हुआ, जिसमें विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री दूसी रामकृष्ण राव जी ने प्रस्तावना रखते हुए कहा कि विद्या भारती के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हमारा मुख्य लक्ष्य है, जिससे वे शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी बिंदुओं को सम्मानित करते हुए, संगठन के लक्ष्यों में कुछ नई बातों को जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है।

इस अवसर पर परम पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत जी ने कार्यक्रम के उद्घाटन में कहा विद्या भारती केवल शिक्षा प्रदान करने का कार्य नहीं करती, बल्कि समाज को सही दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व भारत की ओर देख रहा है उसे मानवता की दिशा देनी होगी।

इस अवसर पर परम पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत जी ने कार्यक्रम के उद्घाटन में कहा विद्या भारती केवल शिक्षा प्रदान करने का कार्य नहीं करती, बल्कि समाज को सही दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व भारत की ओर देख रहा है उसे मानवता की दिशा देनी होगी।

विद्या भारती विचारों के अनुरूप शिक्षा का केंद्र - डॉ. भागवत ने कहा कि विद्या भारती अपने विचारों के अनुरूप शिक्षा कार्य कर रही है। यह शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों के जीवन मूल्यों और संस्कारों का निर्माण भी करती है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा का कार्य व्यापक है, जो केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसका उद्देश्य समाज को नैतिक रूप से समृद्ध बनाना भी है।

युगानुकूल परिवर्तन में निष्क्रिय न रहें - उन्होंने कहा कि समय के अनुसार परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन इसमें निष्क्रिय होकर बैठना उचित नहीं होगा। मानव अपने मस्तिष्क के बल पर समाज में परिवर्तन लाता है और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए

कि यह परिवर्तन सकारात्मक हो।

टेक्नोलॉजी की मानवीय नीति आवश्यक - आज के समय में तकनीक समाज के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल रही है। हमें टेक्नोलॉजी के लिए एक मानवीय नीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक में जो कुछ गलत है, उसे छोड़ना पड़ेगा और जो अच्छा है, उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा।

विविधता में एकता का महत्व - उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विशेषता पर जोर देते हुए कहा कि हमें विविधता में एकता बनाए रखनी होगी। भारत की संस्कृति ने हमेशा सभी को जोड़ने का कार्य किया है, और इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। सब में मैं हूँ, मुझ में सब हैं डॉ. भागवत ने भारतीय दर्शन के इस मूल विचार को रेखांकित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह समाज का अभिन्न अंग है और समाज भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दृष्टिकोण से हमें अपने कार्यों को संचालित करना चाहिए।

विश्व भारत की ओर देख रहा है - आज विश्व भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। भारत ने सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने मूल्यों को बनाए रखा है, और यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि समाज में परिवर्तन लाना है, तो सबसे पहले व्यक्ति में परिवर्तन लाना होगा। उन्होंने विद्या भारती की इस दिशा में भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी, जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक हो।

सभी के कल्याण का उद्देश्य - उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास केवल एक वर्ग या समूह के कल्याण तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें संपूर्ण समाज के कल्याण का लक्ष्य रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी शक्ति और संसाधन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त समाज की उन्नति के लिए समर्पित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में कई विचारधाराएँ हैं और हमें उन लोगों को भी साथ लेकर चलना है जो हमारे विचारों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी का भी मत भिन्न हो सकता है, लेकिन कार्य की दिशा सही होनी चाहिए।

विमर्श का स्वरूप बदलना आवश्यक - डॉ. भागवत ने कहा कि विमर्श का स्वरूप बदलना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमें सकारात्मक सोच और रचनात्मक विचारों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करना चाहिए।

निष्कर्ष - विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री रामकृष्ण राव जी द्वारा प्रस्तुत भूमिका एवं प्रस्तावना से यह स्पष्ट होता है कि विद्या भारती का मुख्य लक्ष्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और शिक्षा को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाना है। परम पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत जी के इस उद्बोधन से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बननी चाहिए।

परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन इसकी दिशा सही होनी चाहिए। विविधता में एकता बनाए रखना, तकनीक की मानवीय नीति बनाना और विरोधियों को भी साथ लेकर चलना-ये सभी बातें समाज को एक नई दिशा देने में सहायक होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों को अपनाते हुए, विद्या भारती इस दिशा में अपने दायित्व को निभाते हुए शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त करने के लिए संकल्पित है। कार्यक्रम में देश भर से अखिल भारतीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी के साथ 700 से अधिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित है।

सिंह बने स्कोप ग्लोबल स्किल्स विवि के कुलगुरु

शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव का अनूठा संगम, युवाओं के कौशल विकास को देंगे नई दिशा

भोपाल। स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी (SGSU) के नए कुलगुरु के रूप में प्रो. (डॉ.) विजय सिंह की नियुक्ति की गई है। प्रो. (डॉ.) विजय सिंह प्रबंधन, शिक्षा, और प्रशासन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जो विश्वविद्यालय में अपने व्यापक अनुभव और अद्वितीय दृष्टिकोण के साथ शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेंगे।

प्रो. (डॉ.) विजय सिंह ने प्रबंधन में पीएचडी, एमबीए, और अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है। वह एक कुशल प्रशासक, उत्कृष्ट शिक्षाविद, और प्रेरणादायक टीम लीडर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार और प्रोफेसर के रूप में 2011 से अपनी सेवाएं दी हैं। इसके पहले उन्होंने डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर में प्रोफेसर के रूप में अपनी भूमिका निभाई।

प्रो. (डॉ.) विजय सिंह ने विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), AICTE, NCTE, BCI, INC, ICAR समेत अन्य नियामक संस्थाओं से संबंधित गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को NAAC ग्रेड एवं छह वर्षों तक लगातार NIRF रैंकिंग प्राप्त हुई।

प्रो. (डॉ.) विजय सिंह के नाम 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित हैं। उन्होंने प्रबंधन विषयों पर 10 पुस्तकों का लेखन और संपादन किया है और उनके नाम पर 2 पेटेंट भी हैं। वह अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप और सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी कर चुके हैं। उनके प्रयासों से रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ एमओयू साइन किए। उनके कुशल प्रबंधन के चलते उन्होंने इन-हाउस ईआरपी प्रणाली विकसित की, जो आईसेक्ट समूह की सभी यूनिवर्सिटीज़ में कार्यरत है।

स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा, प्रो. (डॉ.) विजय सिंह का अनुभव और ज्ञान हमारे छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उनकी नेतृत्व क्षमता और कौशल शिक्षा को लेकर उनकी गहरी समझ विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉ. सितेश कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रो. (डॉ.) विजय सिंह के पास प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव और दूरदृष्टि है। उनकी नियुक्ति से स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक और कौशल विकास प्रयासों में नए आयाम जुड़ने की उम्मीद है।

बीयू में बनाई गई एमपी की पहली 'बी ट्रेल'

मधुमक्खियों के लिए अनुकूल वातावरण किया तैयार, पर्यावरण संरक्षण की पहल

भोपाल। मधुमक्खियों के महत्व को समझते हुए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने मध्य प्रदेश की पहली 'बी ट्रेल' (Bee Trail) स्थापित की है। इस अनूठी पहल का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. एस.के. जैन ने किया। यह बी ट्रेल न केवल मधुमक्खियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएंगी, बल्कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझने में भी मदद करेगी। बी ट्रेल (Bee Trail) एक ऐसा रास्ता या क्षेत्र होता है, जहां मधुमक्खियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, फूल और छत्ते लगाए जाते हैं, जो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं और उनके लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। यह न केवल मधुमक्खियों के संरक्षण में मदद करता है, बल्कि पर्यावरण में परागण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देता है। मधुमक्खियों को अक्सर शहद उत्पादन और उनके डंक के लिए जाना जाता है, लेकिन इनका पर्यावरण में और भी बड़ा योगदान है। मधुमक्खियां पौधों में परागण करके वनस्पतिक जगत को फलने-फूलने में मदद करती हैं। हालांकि, बढ़ते प्रदूषण और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण मधुमक्खियों का अस्तित्व खतरे में है, जिसका प्रभाव कृषि उत्पादन और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने यह बी ट्रेल स्थापित की है। यह पहल विद्यार्थियों को मधुमक्खियों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक

रंग लगाने पर होती है शादी...विदेश से भी आते हैं लोग

● एमपी के आदिवासी इलाकों में शुरू होने वाली है भगोरिया की धूम ● एक-दूसरे को आपस में गुलाल लगाकर करते हैं पसंद का इजहार

भोपाल। मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में होली से पहले भगोरिया पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व आदिवासियों के लिए बेहद खास है और उनकी संस्कृति को दर्शाता है। इसमें युवक-युवतियां एक-दूसरे को पसंद करते हैं और भागकर शादी भी कर लेते हैं। इसके साथ ही यह त्योहार रंगों, संगीत, नृत्य और खरीदारी का भी त्योहार है। विदेशी पर्यटक भी इसे देखने आते हैं, जिनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। भगोरिया, आदिवासियों का एक अनोखा त्यौहार है, जो होली से सात दिन पहले शुरू होता है। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में मनाया जाता है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण युवक-युवतियों का एक-दूसरे को पसंद करना और भागकर शादी करना है। साथ ही, यह त्यौहार संगीत, नृत्य, रंगों और खरीदारी के लिए भी प्रसिद्ध है। भगोरिया हाट में ढोल, मांदल और बांसुरी की धुन पर लोग नाचते-गाते हैं। त्योहार के लिए लोग नए कपड़े, गहने और जरूरत का सामान खरीदते हैं। विदेशी पर्यटक भी इस अनोखे त्योहार का आनंद लेने आते हैं, जिनके लिए सोंडवा गांव में टेंट विलेज बनाया जाता है।

होलिका दहन से सात दिन पहले होती है शुरुआत- भगोरिया पर्व की शुरुआत आम के फूलों की खुशबू के साथ होती है। होलिका दहन से सात दिन पहले से ही आदिवासी इलाकों में बाजार लगने लगते हैं, जिन्हें 'त्योहारिया हाट' या 'सरोडिया हाट' कहते हैं। इन हाटों में लोग त्योहार की तैयारियों के लिए खरीदारी करते हैं। ढोल, मांदल, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र, नए कपड़े, गहने और सजावट का सामान खरीदते हैं। इसीलिए इन हाटों को त्योहारिया हाट कहा जाता है। भगोरिया को प्रेम का त्यौहार भी माना जाता है। हाट-बाजारों में युवक-युवतियां एक-दूसरे को पसंद करते हैं और गुलाल लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। अगर लड़की को लड़का पसंद आता है तो वो भी उसे गुलाल लगाती है।

अगर पसंद नहीं आता तो गुलाल पोंछ देती है। पसंद आने पर दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। गांव वाले फिर दोनों परिवारों से बात करके उनकी शादी करवा देते हैं। शादी होलिका दहन के बाद होती है। यह प्रेम और रिश्तों का अनूठा त्यौहार है। भगोरिया हाट में युवक-युवतियां सज-धज कर आते हैं। भावी जीवनसाथी को ढूंढने का यह उनका अपना तरीका है। लड़का लड़की को पान खाने को देता है। लड़की अगर पान खा ले तो इसे हां मान लिया जाता है। यह रस्म भी अनोखी है। भगोरिया हाट में झूले, चकरी, पान, मिठाई, श्रृंगार का सामान और गहनों की दुकानें लगती हैं। युवक-युवतियां एक-दूसरे को वैलेंटाइन डे की तरह गिफ्ट देते हैं।

पहले भगोरिया हाट से भागने की घटनाएं ज्यादा होती थीं। लेकिन अब शिक्षा और शहरीकरण के कारण इस प्रथा में बदलाव आया है। अब भागने की घटनाएं कम हो गई हैं। भगोरिया की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में कई मत हैं। कुछ किताबों के अनुसार, भगोरिया राजा भोज के समय लगने वाले हाट थे। दो भील राजा, कासूमार और बालून ने अपनी राजधानी भगोर में बड़े मेले और हाट शुरू किए थे। धीरे-धीरे आस-पास के भील राजाओं ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। तब से इन हाट-मेलों को भगोरिया कहा जाने लगा। एक दूसरी मान्यता के अनुसार, इन मेलों में युवक-युवतियां अपनी मर्जी से भागकर शादी करते हैं, इसलिए इसे भगोरिया कहते हैं।

संपादकीय

रोहित पर अनावश्यक विवाद

भारतीय वन डे टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस और कथित रूप से बढ़ते वजन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अनावश्यक टिप्पणी और उस पर छिड़ा राजनीतिक बवाल नहीं होता अगर वो कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता नहीं होतीं। रोहित शर्मा की बॉडी फिटनेस और खेल प्रदर्शन को लेकर हर किसी की अपनी राय हो सकती है। इस नाते डॉ. शमा मोहम्मद ने भी अपना मत जाहिर करके कोई अपराध नहीं किया, लेकिन शमा यह बात भूल गईं कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और बतौर प्रवक्ता उनके द्वारा व्यक्त हर बात को कांग्रेस की राय माना जा सकता है। जाहिर है कि कांग्रेस किसी खिलाड़ी और वो भी रोहित शर्मा जैसे बड़े क्रिकेट खिलाड़ी पर कोई भी टिप्पणी कर जबरन विवाद में नहीं फंसना चाहेगी। क्योंकि इससे कोई राजनीतिक हित नहीं सधता और रोहित देश के अत्यंत लोकप्रिय तथा सम्माननीय खिलाड़ी है। लिहाजा पार्टी ने डॉ. शमा को अपना कमेंट सोशल मीडिया पर से डिलीट करने को कहा। प्रवक्ता डॉ शमा ने उसे हटा भी लिया, लेकिन तब तक राजनीतिक तलवारबाजी शुरू हो चुकी थी। जिसके पीछे खेल भावना कम और राजनीतिक हित साधने का भाव ज्यादा था। हालांकि शमा ने जो पोस्ट डाली थी, उसकी वास्तविकता समझना भी जरूरी है। शमा ने लिखा 'एक खिलाड़ी के लिए मोटा! वजन कम करने की जरूरत है! और निश्चित रूप से, भारत का अब तक का सबसे खराब कप्तान!' उन्होंने रोहित की तुलना भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों से की थी। जिसका मकसद यह बताना था कि रोहित मोटे होने के साथ-साथ उतने बेहतर खिलाड़ी नहीं है। शमा पेशे से डेंटिस्ट हैं और उन्हें क्रिकेट की कितनी समझ है, पता नहीं। लेकिन वो क्रिकेट की प्रशंसक तो हो ही सकती है। जहां तक रोहित के बतौर बैटर परफार्मेंस की बात है तो इस चैम्पियंस ट्रॉफी में उनका कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है। उन्होंने 3 मैचो में मात्र 76 रन ही बनाए हैं। लेकिन कप्तान के रूप में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। उन्होंने अपनी कुशल रणनीति, समझ और दूरदर्शिता के साथ तीनों लीग मैच जीते हैं। इसके अलावा रोहित देश के ऐसे दूसरे कप्तान है, जिनके नेतृत्व में भारत ने पिछले साल टी 20 विश्व कप जीता। शमा ने रोहित की तुलना जिन पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों से की, उनमें से कोई भी भारत को किसी फार्मेट का वर्ल्ड कप नहीं जिता सका है। ऐसे में रोहित को उनसे कमतर ठहराना शमा का पूर्वाग्रह हो सकता है। रहा सवाल सियासत का तो शमा के साथ टीएमसी ने भी रोहित की आड़ में दिल्ली में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर निशाना साधने में कोई देर नहीं की। लेकिन ज्यादातर राजनेताओं ने शमा की टिप्पणी को अनावश्यक बताया। भाजपा ने तो शमा के बयान पर सीधे कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस खेल विरोधी है। गंभीरता से सोचें तो यह पूरा विवाद ही अनावश्यक था। दिक्कत तब खड़ी होती है, जब खेल और खिलाड़ियों के बारे में व्यक्ति की निजी राय को राजनीतिक पार्टी के मुलम्मे में पेश करने की कोशिश की जाती है। यहां राजनीतिक दलों से भी यही अपेक्षा है कि उन्हें अपने प्रवक्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए कि कब कहां और कैसे रिएक्ट करना है। अगर किसी में ऐसी समझ नहीं है तो उसके पार्टी प्रवक्ता होने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वैसे भी खेल और खिलाड़ियों को राजनीति की दलदल में घसीटना और वो भी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर न तो किसी राजनीतिक दल और न ही देश के हित में है।

नजरिया

बलदेव राज भारतीय
लेखक इतिहास प्रवक्ता हैं।

दागी नेताओं के चुनाव लड़ना और लोकतंत्र पर विश्वास

देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को सच्चा देशभक्त मानता है। वह राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियों पर बड़े ज्ञानवर्धक विचार प्रकट करता है और देश में फैले भ्रष्टाचार, अनैतिकता, बेईमानी व रिश्वतखोरी पर कठोर आक्रोश व्यक्त करता है, मानो उससे बड़ा राष्ट्र हितैषी कोई और नहीं। किन्तु, विडंबना यह है कि उसे ये सारी बुराइयाँ केवल दूसरों में ही दिखाई देती हैं, स्वयं में नहीं। वह अपने आपको ईमानदार, सत्यनिष्ठ, निष्कलंक और आदर्शवादी मानता है, जबकि उसके विचार और कर्म प्रायः इसके विपरीत होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लोग अपने दोहरे मापदंडों के कारण राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जिस नैतिकता की अपेक्षा दूसरों से रखते हैं, उसी को अपने आचरण में अपनाने से कतराते हैं।

हमारे देश का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है, जिसकी नींव संविधान और विधि के शासन पर टिकी हुई है। यह प्रणाली नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देती है। लेकिन जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं और कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो यह व्यवस्था के मूल्यों पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न लगा देता है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि दागी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाने की मांग पर विचार होना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया। यह विवाद एक बड़े प्रश्न को जन्म देता है– क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए? या उन्हें संसद और विधानसभाओं में भेजकर कानून बनाने की शक्ति दे देनी चाहिए?

लोकतंत्र का आधार 'जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार' की अवधारणा पर टिका होता है। इसमें प्रत्येक नागरिक को मताधिकार और अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नागरिक, जब तक वह कानूनी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, चुनाव लड़ सकता है और जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हालांकि, यदि जनता के प्रतिनिधि स्वयं गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त हों, तो क्या वे समाज में कानून और न्याय की स्थापना कर सकते हैं? संविधान का उद्देश्य योग्य, ईमानदार और जनसेवा को समर्पित लोगों को शासन में शामिल करना है, न कि वे लोग जो स्वयं कानून तोड़ते हैं।

आज चुनाव लड़ना गरीब व्यक्ति के लिए एक असंभव सपना बन गया है। गांव की सबसे निचली प्रशासनिक इकाई, पंचायत, में सरपंच बनने के लिए भी प्रत्याशी लाखों रुपये खर्च करते हैं, तो विधायक और सांसद बनने के लिए करोड़ों की जरूरत होती है। धन के अभाव में एक आम नागरिक चाहकर भी चुनावी राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकता।

इसके विपरीत, अपराधी प्रवृत्ति के लोग भ्रष्टाचार और अवैध साधनों से अर्जित धन के बल पर न केवल चुनाव लड़ते हैं, बल्कि जेल में रहते हुए भी जीत हासिल कर लेते हैं। विडंबना यह है कि गरीब और शोषित वर्ग, जो स्वयं व्यवस्था परिवर्तन का इच्छुक होता है, भय और दबाव में आकर ऐसे दागी प्रत्याशियों को ही अपना नेता चुन लेता है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के मूल्यों को क्षीण कर रही है और चुनावी प्रक्रिया को धनबल एवं बाहुबल का खेल बना रही है।

देश में कई ऐसे राजनेता हैं जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 43 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें से कई संगीन अपराधों से जुड़े थे, जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण और भ्रष्टाचार। यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाता है, बल्कि जनता का विश्वास भी कम करता है। यदि कोई आम नागरिक मामूली अपराध में भी दोषी पाया जाता है, तो उसे सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। वहीं, जिन पर हत्या, दंगा और घोटालों के आरोप हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं और संसद या विधानसभा का हिस्सा बन सकते हैं। यह असमानता एक गंभीर चिंता का विषय है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावी राजनीति में आपराधिक तत्वों की भागीदारी को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर दागी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया गया, तो यह विधायिका को कमजोर कर देगा और कानून निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। इस तर्क से कई असहमतियां हैं। क्या अपराधी लोगों को राजनीति में रोकने से राजनीति गंदा होने से नहीं बचेगी? अपराधी प्रवृत्ति के लोग किस प्रकार के कानून का समर्थन करेंगे, यह जगजाहिर है। संसद और विधानसभा में बैठने वाले प्रतिनिधियों का नैतिक और कानूनी रूप से स्वच्छ होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया है, तो उसे जनता की सेवा करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मिल भी कैसे सकता है, जो स्वयं अपराधी हो वह समाज सेवा कैसे कर सकता है।

आजीवन प्रतिबंध लगाने का विरोध करने वाले यह तर्क देते हैं कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर चुका है, तो उसे पुनः समाज में योगदान देने का अवसर मिलना चाहिए।

लेकिन, राजनीति कोई साधारण नौकरी नहीं है; यह देश और समाज की सेवा का एक पवित्र कार्य है। यदि सरकारी सेवाओं में नौकरी करने के लिए किसी व्यक्ति का चरित्र प्रमाणपत्र आवश्यक होता है, तो विधायिका में प्रवेश के लिए भी नैतिकता और कानूनी स्वच्छता की कसौटी होनी चाहिए।

चुनाव आयोग को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, जिससे वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर सख्त निर्णय ले सके। ऐसे नेताओं पर चलने वाले मामलों को विशेष न्यायालयों में रखा जाए, ताकि फैसले शीघ्रता से हों और दोषी पाए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित किया जा सके। नेताओं के लिए शिक्षा, ईमानदारी और नैतिकता को अनिवार्य किया जाए। जो नेता स्वयं ईमानदार और देश और संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं होगा तो वह जनता के लिए कैसे और किस प्रकार आदर्श सिद्ध हो सकता है।

चुनाव आयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं मतदाताओं को जागरूक करें कि उन्हें बिना किसी लालच में आए स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को ही चुनना चाहिए। जो भी उम्मीदवार या दल उन्हें किसी प्रकार का लालच या प्रलोभन दें उनकी शिकायत चुनाव आयोग से करें।

लोकतंत्र की सफलता उसके नेताओं की स्वच्छता और जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। यदि राजनीति अपराधियों का अड्डा बन जाएगी, तो यह पूरे शासन तंत्र को भ्रष्ट कर देगी। इसलिए, यह आवश्यक है कि दागी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे और जनता का विश्वास मजबूत हो।

राजनीति

डॉ. सत्यवान सौरभ
लेखक स्तंभकार हैं।

पचास साल बाद होने वाली परिसीमन को लेकर चिंताएँ

उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए अधिक सीटें जोड़ते हुए वर्तमान सीट अनुपात को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के समान एक मॉडल प्रगतिशील राज्यों को नुक़सान पहुँचाए बिना एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सीटों का पुनर्वितरण करते समय, हमें आर्थिक योगदान, विकास मीट्रिक और शासन प्रभावशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने वाले राज्यों को विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जो अच्छे शासन को पुरस्कृत करता है। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और तेजी से बढ़ते राज्यों के प्रभुत्व को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाने चाहिए। संसद के भीतर एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना से कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के हितों की वकालत करने में मदद मिल सकती है।

2031 की जनगणना के बाद एक क्रमिक दृष्टिकोण हितधारकों के साथ चर्चा और एक सहज संक्रमण की अनुमति देगा। किसी भी परिसीमन से पहले, एक राष्ट्रीय आयोग को संभावित प्रभावों का आकलन करना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाने चाहिए। राज्य सरकारों के लिए स्थापित चैनलों के माध्यम से परिसीमन वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेना महत्वपूर्ण है। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी सीट पुनर्वितरण को अंतिम रूप देने से पहले अंतर-राज्य परिषद के साथ अनिवार्य परामर्श होना चाहिए। एक सुनियोजित परिसीमन प्रक्रिया जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को संघवाद की अखंडता से जोड़ सकती है। क्षेत्रीय असमानताओं से बचने के लिए, हमें दोहरे प्रतिनिधित्व मॉडल, भारित मतदान या राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ाने जैसी नवीन रणनीतियों पर विचार करना चाहिए।

राजकोषीय संघवाद और संस्थागत ढांचे को मज़बूत करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजनीतिक निष्पक्षता जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ संरेखित हो, जिससे एक सुसंगत और एकजुट भारत को बढ़ावा मिले। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों का आकार छोटा होगा और शासन में सुधार होगा। संसदीय सीटों को 543 से बढ़ाकर 800 से अधिक करने से संसद सदस्य मतदाताओं की ज़रूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से सम्बोधित कर सकेंगे। निश्चित सीट आवंटन के कारण उत्तरी राज्यों को कम प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ा है और परिसीमन इन ऐतिहासिक असंतुलनों को सुधारने का एक मौका प्रदान करता है।

बिहार का प्रतिनिधित्व अभी भी 1971 के आँकड़ों पर आधारित है, बावजूद इसके कि इसकी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। नवीनतम जनगणना आँकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों को संशोधित करने से लोकतांत्रिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और चुनावी प्रतिनिधित्व में जनसंख्या असमानताओं को रोका जा सकेगा। झारखंड, जिसे 2000 में बिहार से अलग कर दिया गया था, अभी भी पुरानी निर्वाचन संरचना का पालन कर रहा है, जो राजनीतिक स्पष्टता को कम करता है। अधिक आबादी वाले राज्यों से सांसदों की संख्या में वृद्धि विकास सम्बंधी असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नीतिगत हस्तक्षेप अविकसित क्षेत्रों की ओर लक्षित हों। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए अधिक संख्या में सांसदों से बेहतर बुनियादी ढाँचा नियोजन और निवेश का बेहतर आवंटन हो सकता है।

प्रगतिशील राज्यों की घटती भूमिका संघवाद और निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नुक़सान पहुँचाती है। प्रभावी शासन वाले दक्षिणी राज्यों का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे ठोस नीति प्रबंधन के लिए प्रेरणा कम हो सकती है। केरल की उच्च साक्षरता दर से प्रेरित विकास पर्याप्त सीट आवंटन में तब्दील नहीं हो सकता है, जिससे अन्य राज्य समान रणनीति अपनाने से हतोत्साहित हो सकते हैं। अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व केंद्रीकृत नीति निर्माण की ओर रुझान को जन्म दे सकता है, जो क्षेत्रीय शासन स्वायत्तता को प्रतिबंधित कर सकता है। कृषि राज्यों के पक्ष में विधायी समायोजन औद्योगिक क्षेत्रों की ज़रूरतों की उपेक्षा कर सकते हैं, जिससे आर्थिक संतुलन बाधित हो सकता है। यह राजनीतिक पुनर्संरेखण वित्त आयोग द्वारा करों के आवंटन को प्रभावित कर सकता है, जो संभावित रूप से बड़ी आबादी वाले राज्यों के पक्ष में हो सकता है।

अपने महत्वपूर्ण आर्थिक इनपुट के बावजूद, तमिलनाडु और महाराष्ट्र कम प्रतिनिधित्व के कारण अपने राजकोषीय हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। केवल जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व में वृद्धि उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन को बढ़ा सकती है, जिससे क्षेत्रीय तनाव पैदा हो सकता है। तमिलनाडु में राजनीतिक दल परिसीमन के खिलाफ हैं, उन्हें डर है कि अधिक हिन्दी भाषी आबादी वाले राज्यों को सत्ता का नुक़सान होगा, जिससे राजनीतिक परिदृश्य और अधिक विखंडित हो सकता है। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए अधिक सीटें जोड़ते हुए वर्तमान सीट अनुपात को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। राज्यसभा जैसा मॉडल प्रगतिशील राज्यों को नुक़सान पहुँचाए बिना संतुलित दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सीटों का पुनर्वितरण करते समय, हमें आर्थिक योगदान, विकास मीट्रिक और शासन प्रभावशीलता को ध्यान में रखना चाहिए।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने वाले राज्यों को विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जो अच्छे शासन को पुरस्कृत करता है। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और तेजी से बढ़ते राज्यों के प्रभुत्व को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाने चाहिए। संसद के भीतर एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना से कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के हितों की वकालत करने में मदद मिल सकती है। 2031 की जनगणना के बाद एक क्रमिक दृष्टिकोण हितधारकों के साथ चर्चा और एक सहज संक्रमण की अनुमति देगा। किसी भी परिसीमन से पहले, एक राष्ट्रीय आयोग को संभावित प्रभावों का आकलन करना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाने चाहिए। राज्य सरकारों के लिए स्थापित चैनलों के माध्यम से परिसीमन वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेना महत्वपूर्ण है। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी सीट के पुनर्वितरण को अंतिम रूप देने से पहले अंतर-राज्य परिषद के साथ अनिवार्य परामर्श होना चाहिए।

एक सुनियोजित परिसीमन प्रक्रिया जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को संघवाद की अखंडता से जोड़ सकती है। क्षेत्रीय असमानताओं से बचने के लिए, हमें दोहरे प्रतिनिधित्व मॉडल, भारित मतदान या राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ाने जैसी नवीन रणनीतियों पर विचार करना चाहिए। राजकोषीय संघवाद और संस्थागत ढांचे को मज़बूत करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजनीतिक निष्पक्षता जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ संरेखित हो, जिससे एक सुसंगत और एकजुट भारत को बढ़ावा मिले।

बड़े आदमी के साथ सेल्फी से कितने बड़े बन जाते हैं?

व्यंग्य

डॉ. महेन्द्र अग्रवाल
लेखक व्यंग्यकार हैं।

मैं कभी किसी बड़े आदमी के साथ नहीं रहा (ज़रूरत भी नहीं पड़ी) इसलिए उनके बगल में खड़े होकर फोटो मेरा मतलब सेल्फी भी नहीं ले सका। न कभी ऐसा कोई फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दुनिया वालों और अपने साथ के तुच्छ लोगों को अंगूठा जैसा दिखाकर अपने आपको बड़ा आदमी बता सका और न ऐसा करके अपने आप को कभी बड़ा आदमी बना सका। इसका मुझे बहुत भारी अफ़सोस हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन अफसोस इतना भारी तो है कि अब कभी-कभी रात बिरात मैं ही भारी हो उठता हूं और हल्का होने के लिए अनेक वरिष्ठ साहित्यकारों-व्यंग्यकारों जैसे उपक्रम करने पड़ते हैं।

ऐसा नहीं है कि मेरे सम्पर्क में आने-या रहने वाले बड़े आदमी नहीं हैं। हैं बहुत से राजनेता समाजसेवी साहित्यकार कलाकार हैं मगर उनके साथ मेरी फोटो खींचने की इच्छा कभी नहीं हुई क्योंकि इससे मैं छोटा हो जाता।मैं उन्हें पूरी तरह जानता हूं और मानता हूं कि वो अपने कर्मों से बहुत छोटे हैं। कम से कम मुझे तो लगते ही हैं।

ऐसा भी नहीं है कि देश दुनिया में सच्चे अच्छे और बड़े लोगों की कमी है। समाज राजनीति साहित्य संस्कृति और कला के क्षेत्र में आज भी हम गाहे बगाहे अपने से बड़े लोगों से मिलते रहते हैं। यहां तक कि उत्कृष्ट उद्देश्यों वाली साहित्य एवं कला की प्रतिष्ठित अकादमियों के निकृष्ट निदेशकों से भी।

यों बड़े लोग पहले भी मिलते थे।मगर तब बहुउपयोगी (मल्टीपरपज़) मोबाइल हाथ में नही होते थे। मतलब इतनी आसानी से सेल्फी लेने की सुविधा हमारे अपने हाथों में नहीं थी।अपना हाथ जगन्नाथ।अब तो किसी को पता भी नहीं पड़ता कि वे कब किसकी सेल्फी में चाहे अनचाहे कै़द हो गये हैं।शायद सुलभ शौचालयों की तरह इतनी सुलभ सुविधा ही हमारी भौतिक सभ्यता का मंतव्य और गंतव्य है।इसका लाभ उठाकर हम अपने समस्तरीय और अधोस्तरीय लोगों को उनकी तुच्छता का बोध आसानी से करा सकते हैं।लेकिन इस कारण कई बार विवाद भी उठ खड़े होते हैं कि फलाने की सेल्फी फलाने गुंडे बदमाश या गलत आदमी के साथ क्यों है

महत्वोन्मादी सिद्ध और प्रसिद्ध जन प्रसिद्धि व प्रसाद की आकांक्षा में बड़े-बड़े मंत्रियों के साथ सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने को मरे जाते हैं। बस मरते ही नहीं है क्योंकि उन्हें इससे पहले की अपनी सेल्फी भी अपलोड करनी होती है। देश और प्रदेश की तो बात ही अलग है किन्तु जिले में कलेक्टरएस. पी. के साथ की सेल्फी भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती। जिला स्तरीय साहित्यकार, प्रशासनिक कर्मचारी और अन्य अवसरानुकूल लाभाकांक्षी उससे ही अपने को धन्य समझते हैं। इससे तो आजकल नए और छुटभैये पत्रकार भी गौरवान्वित हो रहे है। जिले के अधिकारियों पर पकड़ भी बनती है और पैसा भी।फ्री फंड में फालतू रुतबा तो गांठ ही लेते हैं।

बड़े आदमी के साथ सेल्फी से कितने बड़े बन जाते हैं? इसका कोई स्पष्ट पैमाना नहीं है। कई बार दांव उल्टा पड़ जाता है।कई बार ऐसा भी हुआ कि जिन संतों के साथ की फोटो लगाये घूमते थे उनके जेल जाने के बाद अपना ही मुंह छिपाने की नौबत आ गई। जिन मंत्रियों के साथ की सेल्फी लोड की दूसरे ही दिन उनके कारनामों की सी. डी. सामने आ गई। तब लगता है साल छह महीने सब्र कर लेते तो बेहतर होता।पर क्या करें आदत से मजबूर हैं। कारण मान्यता है (संजय दत्त वाली नहीं) कि मेल पर भेजी सामग्री या फेसबुक पर अपलोड फोटो -मैटर कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए यह भी अमर होने की दिशा में उठाया गया हमारा ठोस कदम है।बिना अमृत पिये, बिना अमृत के लिए समुद्र मंथन किये,या बिना अमृत के लिए युद्ध किये। मूल मंत्र जो सिद्ध कर लिया-सेल्फी विद बड़े आदमी।

शुरू में लगा कि सेल्फी विद बड़े आदमी ,चाय विद सी एम जैसा राजनीतिक टोटका या ,काफी विद अमीन सयानी जैसा फिल्मी नाटक है।वो तो बाद में समझ आया कि ये रातों रात बड़ा आदमी या सेलिब्रिटी बनने का नया फंडा है और इन दिनों खासो आम में बहुत पापुलर है।फेसबुक पर चल भी रहा है भले ही उस समय की फेस रीडिंग से भट्ठा बैठ रहा हो।मेरे एक मित्र की एक फोटो एक फोटोग्राफर की दुकान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई थी।जिसमें वो एक नामधारी मुख्यमंत्री के साथ खड़े थे।बिल्कुल क्लोजअप में।मगर गौर से देखने पर दिख ही जाता था कि वह बात करने की कोशिश कर रहे हैं किन्तु सी. एम. साहब उन्हें तवज्जो देने के बजाय किसी और को देख रहे हैं। अब इसे क्या कहें-बोलती तस्वीरें भ्रम फैलाते लोग झूठ का पर्दाफाश ! नंगी हक़ीकत या सेल्फी विद बड़े आदमी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

अशोक व्यास
लेखक व्यंग्यकार हैं।

शमशान वैराग्य किस चिड़िया का नाम है

जीवन में जब भी किसी को पहली बार वैराग्य लेने का विचार आया होगा तब शमशान या कब्रिस्तान ही एसी जगह होगी जहाँ जाने पर शमशान वैराग्य की घटना घटे या ना घटे पर एक बार विचार जरुर आता है कि छोड़ो इस दुनियादारी को इसमें कुछ नहीं रखा है . जैसा कि महात्मा बुद्ध ने जिन आर्य सत्यों को कहा उनमे से एक आर्य सत्य यह है कि '' जीवन है '' और जीवन है तो मरना जीना लगा ही रहता है . जब कोई मरता है तो मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता लेकिन उसके मरे गिरे में उसको अंतिम विदाई देने जरुर जाया जाता है . शव के साथ शमशान यात्रा में जाने के शोक के अवसर पर जैसे ही बड़े बड़े अक्षरों में शमशान घाट के द्वार पर रंगीन पेंट से लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिये वहां पर आजकल शमशान घाट नहीं मुक्तिधाम लिखा रहता है . जिसे पढ़ते ही आत्मा में एक रोमांच सा पैदा होने लगता है शरीर में फुरफुरी सी दौड़ने लगती है . कपाल क्रिया के बाद पञ्च लकड़ी या कब्रिस्तान में हो तो मिटटी डालने के बाद तो कसम से सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यास लेने की इच्छा बहुत जोर से जोर मारने लगती है जिसे बड़ी मुश्किल से दबाना पड़ता है . लेकिन वहां रहकर सभी क्रियाकर्म देख कर जब श्रद्धांजली के बाद शरीर की शुद्धि के लिये अपने शरीर पर पानी छिड़कते है तो यूं समझिये कि वैराग्य की जलती आग पर पानी डालकर ठंडा कर दिया हो . द्वार से बाहर निकलते ही वही बाल , वही बच्चे , वही बाजार वही रिश्तेदार , वही भाव ताव , वही मोबाइल सम्मोहन याद रह जाता है . वैराग्य के भाव शव पर डाले गए कपूर की तरह उड़ जाते हैं या नमक की तरह गल जाते हैं . लेकिन पुराने टाइप के शमशान घाट को छोड़ कर नए आधुनिक कब्रिस्तान और सौंदर्यीकरण किये हुए मुक्ति धाम में इस तरह के विचार मन में लाना एक तरह से वर्जित हो जाता है . आधुनिक मुक्तिधाम में एक पोजिटिविटी आत्मा में प्रवेश करने लगती है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या की धारणा मिथ्या लगने लगती है . अगर आप भी किसी आधुनिक मुक्तिधाम का भ्रमण कर लें तो संसार असार नहीं असरदार भी है ऐसी भावना बलवती होने लगेगी . इस आधुनिक मुक्ति धाम में आकर वैराग्य के विचार हवा हो जाते हैं क्यों की शमशान जबसे आधुनिक होकर मुक्तिधाम बनकर नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे हैं तबसे शमशान में वैराग्य नहीं घटता है और वह अपग्रेड होकर वैराग्य से मुक्ति के केंद्र बनते जा रहे है , लेकिन रुकिए अभी विवरण में ट्विस्ट आना बाकी है .

देश का विकास हो ना हो लेकिन आजकल शमशान जिसे सम्मान से मुक्तिधाम कहते हैं में प्रायोजित विकास का अंधाधुन दौर चल रहा है और होना भी चाहिए आखिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इनको भी स्मार्ट बनाने का पूरा पूरा हक़ है . शहर के प्रसिद्द और वर्तमान के मुख्य दर्शनीय स्थल मुक्तिधाम के ए सी सभागार में मुक्तिधाम प्रबंध और विकास समिति की बैठक होने वाली थी . आज का एजेंडा था कि मुक्तिधाम के विकास के लिये एसा और क्या किया जाय कि मुर्दों के साथ आने वाले जीवित व्यक्तियों को यहाँ बार बार आने की कामना तो हो लेकिन एसा ना हो कि यहाँ असार संसार से मुक्ति की कामना होने लगे . हमें एसा पोजिटिव माहोल यहाँ देना चाहिए की जीने की चाह बनी रहे तभी तो मानव आगे बढ़ेगा विकास करेगा सभी भगवा पहन लेंगे तो संसार नीरस हो जायेगा . मुक्तिधाम प्रबंध और विकास समिति की बैठक के एजेंडे में यहएक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जिसे सबने एक मत से स्वीकार कर लिया था. अब तक के विकास कार्यों जिसे आधुनिकीकरण भी कह सकते है जिसमे शेड बन गया था , श्रद्धांजलि देने और दो मिनट मौन रखने के लिये बड़ा सा लोकसभा माफ़ कीजिये शोकसभा हाल भी बना दिया था , धार्मिक पुस्तकों में लिखे सूत्र वाक्य दीवारों पर लिख दिए गए थे, वृक्षरोपण क्षमा करें आजकल सही शब्द पौधा रोपण हो गया था वही पौधे अब वृक्ष बनने के लिये आतुर होने लगे है यानि बड़े होने लग गए हैं . जैसे पौधे वृक्ष बन गए थे वैसे ही विकास कार्य को भी बड़ा होना चाहिए इसी सोच के कारण एक सदस्य ने सुझाव दिया कि मुक्तिधाम में जगह जगह स्पीकर लगा देना चाहिए जिसमें भगवान के भजन चलते रहे या राम नाम सत्य की गूंज सुनाइ देती रहे उससे मरने वाले की आत्मा को शांति और उनके साथ आने वालों को राम नाम सत्य बोलने में मेंहनत नहीं करनी पड़ेगी और उनकी आत्मा भी पश्चाताप नहीं करेगी कि इतने सारे लोग आये है पर राम नाम सत्य है की अनुगूँज सुनाइ नहीं दे रही है . पार्थिव शरीर चार कन्धों पर जाता है तब वह चार लोग क्या कहेंगे जैसी बातों से अंतिम समय में भी मुक्त नहीं हो पाता हैं क्यों कि चार लोग चार बातें करने के लिये चार मिनट का समय निकाल ही लेते हैं आखिर अंतिम संस्कार होने तक समय बिताना भी एक काम है . कई ज्ञानी बात को इस प्रकार शुरु करते हैं '' दिवंगत ने बड़े अच्छे कर्म किये थे जो बच्चों ने बहुत सेवा करी एसा कोई डाक्टर नहीं छोड़ा जिसको नहीं दिखाया हो . दूसरे ने डाक्टरों द्वारा की जा रही लूट को मुद्दा बनाते हुए कहा '' आजकल तो साहब भगवान का दर हो या डॉक्टर का चेंबर उस में जूते पहनकर जाना श्रद्धा का अपमान है सुख के सब साथी लेकिन दुःख में तो इन्ही दोनों की याद आती है दोनों जगह भेंट चढ़ाना जरुरी है . स्वास्थ्य खराब होने पर पहले नीचेवाले यानि डाक्टर का और कोई भी मुसीबत आने पर उपर वाले के नाम का उच्चारण अपने आप होने लगता है . बीमारी पर इतना खर्च करने के बाद भी डॉक्टर कहता है ऊपर वाले पर भरोसा रखो '' . मृतक की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर तीसरा बात को अलग मोड़ देते हुए कहेगा '' कोई भी मुसीबत में भगवान के दर पर माथा टेकने जाना ही पड़ता है और बीमारी मे डाक्टर के दर पर दंडवत करना पड़ता है लेकिन सभी इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते है ऐसे टाइम अगर आयुष्मान कार्ड नहीं हो तो झोलाछाप डॉक्टर से इंजेक्शन या ग्लूकोज की बोतल का टॉप अप डलवा लेना चाहिए एक तरह से बीमार आदमी रिचार्ज हो जाता है और उम्मीद है तीन बाय छेह की जगह पहुंचने तक इन्सान को यही काम करना है ''

चार कन्धों पर लेटकर पञ्च तत्वों से मिलने का सोभाग्य प्राप्त करने के लिये भी पंचों का अंतिम उद्बोधन भी सुनना बेहद जरुरी है . उस समय दिवंगत की प्रशंसा , बीमारी , डाक्टर का इलाज , बच्चों द्वारा सेवा करना पंचों के प्रिय विषय होते हैं . अब आप ही बताएं ऐसे माहोल और ऐसे दर्शनीय स्थान पर ज्ञान ध्यान की बातों पर कौन कान देता है अतः वैराग्य क्या खा कर आएगा , मजाल है जो शमशान में वैराग्य घट जाये वैसे भी हर कम सटासट करने वाली पीढ़ी को क्या मालूम कि शमशान वैराग्य किस चिड़िया का नाम है ?

लोकपर्व

भगोरिया : आदिवासी लोक संस्कृति और आस्था का पर्याय

भगोरिया अपनी अनूठी परंपराओं, उत्सवी माहौल और सामाजिक महत्व के कारण विशेष पहचान रखता है। इस पर्व का प्रमुख आकर्षण युवाओं का आपसी मेल-जोल, पारंपरिक नृत्य-संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और व्यापारिक मेलों में देखने को मिलता है। भगोरिया पर्व की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मान्यताएँ प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार, इस पर्व की शुरुआत भील राजा काशीराज (या भगोर) ने की थी। कहा जाता है कि यह पर्व पहले एक सैन्य आयोजन के रूप में शुरू हुआ था, जहाँ राजा अपनी सेना को एकत्र करता था और अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारियों के लिए प्रशिक्षित करता था। धीरे-धीरे यह आयोजन सामाजिक मेल-मिलाप और आनंदोत्सव में बदल गया और आज यह भील जनजाति का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है।

संध्या राजपुरोहित

लेखक पत्रकार हैं।

पिछले कुछ समय से जनजातीय कार्य विभाग के साथ धार जिले के आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसी दौरान आदिवासी समुदाय के बीच मे रहकर उनकी दिनचर्या, रहन सहन संस्कृति को भी करीब से देखने और जानने का मौका मिला। कार्य के सिलसिले में जब अलग अलग रहवासी इलाकों में जाना हुआ तो स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान बहुत करीब से मेरी समझ बनी कि देश की सांस्कृतिक विविधता में आदिवासी समाज का योगदान अविस्मरणीय है। उनकी परंपराएँ, त्योहार और रीति-रिवाज न केवल उनके समाज की पहचान हैं, बल्कि उनकी आस्था और जीवनशैली का भी अभिन्न हिस्सा हैं। इन्हीं पारंपरिक उत्सवों में से एक महत्वपूर्ण पर्व है भगोरिया, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के भील और भिलाला जनजातियों का एक विशिष्ट और रंग-बिरंगा उत्सव है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, स्वतंत्रता, सामाजिक मेलजोल और आनंद का प्रतीक भी है। इस पर्व का महत्व केवल आदिवासी समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की लोक संस्कृति की एक अनमोल धरोहर बन चुका है।

भगोरिया अपनी अनूठी परंपराओं, उत्सवी माहौल और सामाजिक महत्व के कारण विशेष पहचान रखता है। इस पर्व का प्रमुख आकर्षण युवाओं का आपसी मेल-जोल, पारंपरिक नृत्य-संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और व्यापारिक मेलों में देखने को मिलता है।

भगोरिया पर्व की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मान्यताएँ प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार, इस पर्व की शुरुआत भील राजा काशीराज (या भगोर) ने की थी। कहा जाता है कि यह पर्व पहले एक सैन्य आयोजन के रूप में शुरू हुआ था, जहाँ राजा अपनी सेना को एकत्र करता था और अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारियों के लिए प्रशिक्षित करता था। धीरे-धीरे यह आयोजन सामाजिक मेल-मिलाप और आनंदोत्सव में बदल गया

और आज यह भील जनजाति का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है।

एक और मान्यता के अनुसार, यह पर्व भील समाज की प्रेम विवाह परंपरा से जुड़ा हुआ है। यह उत्सव युवाओं को अपने जीवनसाथी चुनने का अवसर प्रदान करता है। इस मेले में युवक-युवतियाँ सज-धजकर आते हैं और यदि वे एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो गुलाल लगाकर अपने प्रेम का इज़हार करते हैं। यदि दोनों सहमत होते हैं, तो वे परिवार की अनुमति के बिना भी विवाह कर सकते हैं, जिसे बाद में समाज द्वारा मान्यता दी जाती है। इसी कारण इसे भगोरिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है 'भागकर विवाह करने की परंपरा' कहते है कि महाशिवरात्री पर गुलाल उड़ा दिया जाता है वही से आगाज होता है भगोरिया पर्व का । यह पर्व फाल्गुन मास में होली से एक सप्ताह पूर्व शुरू होता है और लगभग सात दिनों तक चलता है। यह एक दिन का निश्चित पर्व नहीं होता, बल्कि इसे विभिन्न गाँवों और कस्बों में अलग-अलग दिनों में मनाया जाता है। यह परंपरा इस तरह बनाई गई है कि आदिवासी समुदाय के लोग पूरी तरह से शामिल होकर विभिन्न स्थानों पर इस मेले का आनंद ले सकें ।

भगोरिया पर्व अपने उत्सवमय माहौल और सांस्कृतिक रंगों के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला रंगों, संगीत, नृत्य और पारंपरिक पहनावे से सराबोर रहता है। भील और भिलाला जनजाति के लोग अपने पारंपरिक वाद्ययंत्र जैसे मांदल, बांसुरी, थाली और ढोल बजाकर सामूहिक नृत्य करते हैं। इस मेले में गुलाल और अबीर की वर्षा होती है, जिससे न सिर्फ आसमान रंग से सराबोर होता है अपितु सारा वातावरण पूरी तरह होली के रंग में रंगा हुआ प्रतीत होता है। इस अवसर पर पुरुष और महिलाएँ पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। महिलाएँ विशेष रूप से रंगीन घाघरा-चोली और साड़ी पहनती हैं और पारंपरिक गहनों से खुद को सजाती हैं। पुरुष चटक रंगों की पगड़ी, धोती और कुर्ता पहनते हैं। भगोरिया मेले में पुरुषों की रंगीन पगड़ी सबसे खास पहचान मानी जाती है, जो उनकी संस्कृति और परंपरा का बोध करती है।

भगोरिया पर्व का सबसे दिलचस्प और अनूठा पहलू इसकी प्रेम विवाह परंपरा है। इस पर्व को युवाओं के मिलन का त्योहार भी कहा जाता है। इसमें युवक और युवतियाँ मेले में आते हैं, एक-दूसरे को पसंद करते हैं और यदि सहमति होती है, तो वे भागकर विवाह कर लेते हैं। यह परंपरा पूरी तरह से सामाजिक मान्यता प्राप्त है और वर्षों से चली आ रही है। यदि परिवार इस विवाह को स्वीकार नहीं करता, तो भी समाज इसे पूरी तरह से स्वीकृति देता है। यही कारण है कि इसे 'भगोरिया', अर्थात 'भागने की परंपरा' के रूप में जाना जाता है।

इस पर्व की शुरुआत गाँव के प्रमुख देवस्थानों और ग्राम देवताओं की पूजा से होती है। ग्रामीण समाज के लोग मिलकर अपने कुलदेवताओं की आराधना करते हैं और फिर पूरे हर्षोल्लास के साथ मेले में भाग लेते हैं। भगोरिया पर्व धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भील समुदाय प्रकृति पूजक होता है और इस पर्व के दौरान वे अपने ग्राम देवताओं, कुलदेवताओं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस अवसर पर गाँवों के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है, जिसमें पूरा समुदाय सम्मिलित होता है।इस पर्व में जल, वृक्ष और पशुओं की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। आदिवासी समाज प्रकृति को अपना संरक्षक मानता है और इस पर्व के माध्यम से वे अपनी परंपरागत आस्थाओं को और मजबूत करते हैं।

हालाँकि, आधुनिकता और वैश्वीकरण के प्रभाव से इस पर्व की मौलिकता पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है। अब यह केवल प्रेम विवाह तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें व्यावसायिक गतिविधियाँ भी अधिक हो गई हैं। बावजूद इसके, यह पर्व आज भी भील और भिलाला समाज की संस्कृति, आस्था और पहचान का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। भगोरिया पर्व केवल एक मेला नहीं, बल्कि यह आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह पर्व प्रेम, आनंद, मेल-जोल और परंपराओं का संगम है, जिसे भील और भिलाला समुदाय अपनी संस्कृति की पहचान और गौरव के रूप में मनाते हैं। इस पर्व की खासियत यह है कि यह परंपरागत प्रेम विवाह, सामाजिक मेलजोल, व्यापारिक गतिविधियों और धार्मिक आस्था को एक साथ समेटे हुए है। भगोरिया, भारतीय लोकसंस्कृति की एक ऐसी अमूल्य धरोहर है, जो सदियों से अपनी जीवंतता, रंगों, संगीत और सामाजिक सौहार्द्र के साथ आने वाले कई वर्षों तक अपनी पहचान बनाए रखेगी

मध्य प्रदेश : प्रकृति के सफाई कर्मियों का 'स्वर्ग'

गिद्धों की छवि अक्सर नकारात्मक अर्थों को दर्शाती है, लेकिन ये पक्षी लोककथाओं के भयावह प्राणियों से बहुत दूर है। इसके बजाय, वे प्रकृति के गुमनाम नायक हैं, जो एक महत्वपूर्ण स्वच्छता सेवा प्रदान करते हैं। सफाईकर्मी के रूप में, वे पशु शवों का कुशलतापूर्वक निपटान करते हैं, जिससे एंथ्रेक्स और तपेदिक जैसे रोगों के प्रसार के रोक का नैसर्गिक उपक्रम है। उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ वातावरण में योगदान करती है, जो वन्यजीवों और मानव जनसंख्या सुरक्षा, दोनों के लिए लाभप्रद है। हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश ने अपनी गिद्ध आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। 2019 में, राज्य के वन विभाग ने 8,397 गिद्धों की गिनती की। 2021 तक, यह संख्या बढ़कर 9,446 हो गई, और 2024 में, यह 10,845 तक पहुंच गई। अब, आबादी 13,000 के करीब पहुंच रही है, आधिकारिक गिनती 12,981 है। यह उछाल राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित ठोस संरक्षण पहलों और वन अधिकारियों और वन्यजीव उत्साही लोगों द्वारा किए गए समर्पित कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम है।

डॉ. तेज प्रकाश व्यास

(प्रकृति एवं वन्यजीव वैज्ञानिक तथा पूर्व प्राचार्य)

मध्य प्रदेश, जो पहले से ही 'बाघ राज्य' और 'हीरा राज्य' के रूप में विख्यात है, ने अब एक और महत्वपूर्ण उपाधि अर्जित की है: 'गिद्ध राज्य।' हालिया अनुमानों के अनुसार, यह राज्य भारत में इन महत्वपूर्ण सफाईकर्मियों की सबसे बड़ी आबादी का घर है, जिसकी संख्या 13,000 हो गई है। यह उल्लेखनीय पुनरुत्थान राज्य के संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है,साथ ही पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में गिद्धों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

गिद्धों की छवि अक्सर नकारात्मक अर्थों को दर्शाती है, लेकिन ये पक्षी लोककथाओं के भयावह प्राणियों से बहुत दूर है। इसके बजाय, वे प्रकृति के गुमनाम नायक हैं, जो एक महत्वपूर्ण स्वच्छता सेवा प्रदान करते हैं। सफाईकर्मी के रूप में, वे पशु शवों का कुशलतापूर्वक निपटान करते हैं, जिससे एंथ्रेक्स और तपेदिक जैसे रोगों के प्रसार के रोक का नैसर्गिक उपक्रम है। उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ वातावरण में योगदान करती है, जो वन्यजीवों और मानव जनसंख्या सुरक्षा, दोनों के लिए लाभप्रद है।

हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश ने अपनी गिद्ध आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। 2019 में, राज्य के वन विभाग ने 8,397 गिद्धों की गिनती की। 2021 तक, यह संख्या बढ़कर 9,446 हो गई, और 2024 में, यह 10,845 तक पहुंच गई। अब, आबादी 13,000 के करीब पहुंच रही है, आधिकारिक गिनती 12,981 है। यह उछाल राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित ठोस संरक्षण पहलों और वन अधिकारियों और वन्यजीव उत्साही लोगों द्वारा किए गए समर्पित कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम है।

एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा, 'गिद्धों की संख्या में वृद्धि इन पक्षियों के विशाल और शक्तिशाली लाभों का परिणाम है, जिसमें सफाईकर्मी के रूप में उनकी भूमिका भी शामिल है। हमने उनके लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, और परिणाम अब स्पष्ट हैं।'

2016 में, मध्य प्रदेश सात विभिन्न प्रजातियों के गिद्धों का घर था,

जिसमें चार निवासी और तीन प्रवासी प्रजातियां शामिल थीं। यह विविधता गिद्ध आवास के रूप में राज्य के महत्व को उजागर करती है। जबकि समग्र जनसंख्या वृद्धि उत्साहजनक है, जबलपुर जैसे कुछ क्षेत्रों में स्थानीय गिरावट देखी गई है, जो यह दर्शाता है कि निरंतर निगरानी और लक्षित संरक्षण उपायों की अभी भी आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश में गिद्ध संरक्षण की सफलता की कहानी इन पक्षियों के लिए आशा प्रदान करती है, जिन्होंने डिक्लोफेनाक (एक पशु चिकित्सा दवा) से विषाक्तता, आवास हानि और भोजन की कमी जैसे कारकों के कारण हाल के दशकों में पूरे एशिया में गिद्धों के खतरनाक गिरावट का सामना किया है। इन महत्वपूर्ण सफाईकर्मियों की रक्षा के लिए राज्य की प्रतिबद्धता न केवल इसकी समृद्ध जैव विविधता को लाभ पहुंचाती है, बल्कि एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में गिद्धों के महत्व को भी उजागर करती है।

अंतिम संदेश: गिद्ध संरक्षण के प्रति मध्य प्रदेश का समर्पण देश के बाकी हिस्सों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित करता है। इन पक्षियों द्वारा निभाई गई अमूल्य भूमिका को पहचानकर, राज्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और अधिक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित कर रहा है।

'गिद्ध राज्य' की उपाधि केवल संख्याओं की मान्यता नहीं है, बल्कि प्रकृति के महत्वपूर्ण सफाई दल को संरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

पुस्तक समीक्षा

अम्मा: आदर्शवादी और करिश्माई व्यक्तित्व की झलक

इस उपन्यास की विषयवस्तु एक केंद्रिय पात्र 'अम्मा' के ईर्दगर्द बुनी गई है तथा एक चलचित्र की तरह पाठक के सामने आती है. फ्लेशबेक के रुप में प्रारम्भ इस उपन्यास के सूत्रधार को नईदिल्ली के प्लेटफार्म पर एक वृद्ध महिला अश्रुप्रवाहित करती दिखाई देती है और करुणा का भाव उसे आकृष्ट करता है. वैधव्य को प्राप्त और अपनो द्वारा अपने घर से निष्कासित महिला को वह अपने घर हैदराबाद ले आता है. घर के वातावरण में घुलमिलकर वह परिवार का अविभाज्य व जरुरी हिस्सा बन जाती है. सूत्रधार अपने बैंकिंग के स्वंय सहायता समूह के अनुभव अम्मा से साझा करता है तथा इससे अम्मा को काम की एक नई दिशा प्राप्त होती है. महिलाओं के समूह बनाकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाने की पहल उसे एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता तक ले जाती है. शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र की विसंगतियों समेत महिलाओं, दिव्यांगों, अनाथों, गरीबों, मेहनतकशों की समस्याओं की ओर उपन्यास के माध्यम से ध्यान आकृषित किया गया है. लोककल्याण की योजनाओं के क्रियांवयन की कमजोरियों को रेखांकित किया गया है.

सुरेश उपाध्याय

समीक्षक

'अम्मा', न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली से प्रकाशित उपन्यास है. लेखक, समीक्षक, लघुकथाकार, व्यंग्यकार श्री दीपक गिरकर के इस उपन्यास के पूर्व बैंको के एन पी ए के संदर्भ में एक सुझावात्मक पुस्तक (एन पी ए एक लाइलाज बिमारी नही) के अतिरिक्त एक व्यंग्य संग्रह (बंटी, बबली और बाबूजी का बटवा), आलेख संकलन (नीव के पत्थर), लघुकथा पर आलोचनात्मक पुस्तक (उत्कृष्ट लघुकथा विमर्श) प्रकाशित हुए हैं. एक समीक्षक के रुप में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में साहित्य की विभिन्न विधाओं यथा कविता, कहानी, उपन्यास, व्यंग्य, वैचारिक आलेख आदि पर उनकी समीक्षाए लगातार प्रकाशित हो रही है.

इस उपन्यास की विषयवस्तु एक केंद्रिय पात्र 'अम्मा' के इर्दगर्द बुनी गई है तथा एक चलचित्र की तरह पाठक के सामने आती है. फ्लेशबेक के रुप में प्रारम्भ इस उपन्यास के सूत्रधार को नईदिल्ली के प्लेटफार्म पर एक वृद्ध महिला अश्रुप्रवाहित करती दिखाई देती है और करुणा का भाव उसे आकृष्ट करता है. वैधव्य को प्राप्त और अपनों द्वारा अपने घर से निष्कासित महिला को वह अपने घर हैदराबाद ले आता है. घर के वातावरण में घुलमिलकर वह परिवार का अविभाज्य व जरुरी हिस्सा बन जाती है. सूत्रधार अपने बैंकिंग के स्वय सहायता समूह के अनुभव अम्मा से साझा करता है तथा इससे अम्मा को काम की एक नई दिशा प्राप्त होती है. महिलाओ के समूह बनाकर उन्हे

आत्मनिर्भर बनाने की पहल उसे एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता तक ले जाती है. शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र की विसंगतियो समेत महिलाओं, दिव्यांगों, अनाथो, गरीबों, मेहनतकशों की समस्याओं की ओर उपन्यास के माध्यम से ध्यान आकृषित किया गया है. लोककल्याण की योजनाओ के क्रियांवयन की कमजोरियों को रेखांकित किया गया है. अम्मा एक करिश्माई व्यक्तित्व की तरह इस उपन्यास में उभरकर आती है तथा सामाजिक व चेरिटिबल संस्थाओं के माध्यम से इन खामियों को दूर करने में सफल होती है. अम्मा का एक रुप आंदोलनकारी का भी उपन्यास में दर्शाया गया है और वक्त जरुरत आंदोलन के माध्यम से भी वह कामयाबी हासिल करती है. जनता का उसके प्रति विश्वास व समर्थन राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्र में भी उसकी अहमियत बढ़ाता है और उसकी मांग को अनसुना करना किसी के लिए आसान नही होता है. अम्मा की सक्रियता व प्रतिष्ठा उसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के साथ पदम पुरस्कारों से अलंकृत करती है तथा राज्यसभा की सदस्यता के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं (जिसे वह विनम्रता से अस्वीकार करती है). सूत्रधार के परिवार को व्यवस्थित चलाने में मदद के साथ वह उनके भविष्य को संवारने में भी प्रभावी भूमिका अदा करती है. अम्मा के अवसान के बाद सूत्रधार की बेटी उनके काम को आगे बढाने का कार्य करती है और इन गतिविधियो की निरंतरता के प्रति आश्वस्त करती है..

आदर्शवादी दृष्टिकोण और सामाजिक रुपांतरण में करिश्माई व्यक्तित्व की भूमिका इस उपन्यास की भावभूमि है. परस्पर मानवीय सम्बंधों तथा दया, ममता, करुणा, प्रेम, सहयोग, सामंजस्य जैसे जीवन मूल्यों को रेखांकित करने का प्रयास उपन्यास में किया गया है. पारिवारिक मूल्यों की महत्ता व गरिमा को प्रतिष्ठित करने के प्रयास भी उपन्यास में किए गए हैं. उपन्यास में हमारे समय की पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सम्स्याओं की जटिलताओं को सहजता से हल करने के प्रयास रेखांकित किए गए हैं.

भाषा की सहजता, सरलता व चित्रात्मता पढ़ने की लय में सहायक होती है तथा तेलगु भाषा का वृहद प्रयोग विस्मित करता है. इस उपन्यास को डायरी व संस्मरण की मिलिजूली शैली का कहा जा सकता है.

'अम्मा' उपन्यास का स्वागत करते हुए मैं श्री दीपक गिरकर को बधाई देता हूं तथा आशांवित हूँ कि पाठकों का स्नेह व विश्वास उन्हे अर्जित होगा..

उपन्यास : अम्मा
लेखक : दीपक गिरकर
प्रकाशक : न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली
मूल्य : रु. 225/

संक्षिप्त समाचार

जिला सलाहकार समिति की बैठक सात को

विदिशा (निप्र)। गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक सात मार्च को आयोजित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के चेम्बर में दोपहर 12 बजे से आयोजित जिला सलाहकार समिति की बैठक में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत नवीनीकरण एवं नवीन पंजीयन हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा कर निर्णय लिए जाएगें।

एनएचएआई की 1033 हेल्पलाइन सेवा

विदिशा (निप्र)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की 1033 हेल्पलाइन राष्ट्रीय राजमार्गों से यात्रा करने वाले सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए 24 घंटे सातों दिवस सहायता सेवा प्रदान कर रही है। यह हेल्पलाइन दुर्घटनाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 1033 हेल्पलाइन को टोल प्लाजा, एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन, क्रेन जैसी अन्य राजमार्ग संचालन सुविधाओं के साथ एकीकृत किया गया है। जिससे जरूरत के अनुसार आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। सड़क उपयोगकर्ताओं की सभी कॉल्स का उत्तर तत्काल दिया जाता है, जिससे उनका सफर अधिक सुरक्षित और सुगम बनता है। 1033 हेल्पलाइन की सहायता से किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही, किसी भी दुर्घटना स्थल पर गोल्डन ऑवर के भीतर पहुंचकर मृत्यु-दर को कम किया जा रहा है। यह सेवायें सड़क उपयोगकर्ताओं के विश्वास को मजबूत कर रही है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को अधिक सुविधा जनक बना रही है।

अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की वीरगाथा का चित्रण

सीहोर (निप्र)। अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की स्मृति और उनकी वीरगाथा को जीवंत बनाये रखने के लिए सीहोर नगर पालिका द्वारा टाउन हाल के पास कुंवर चैन सिंह द्वारा अंग्रेजो से युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य को सुन्दर और आकर्षक पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। वीर शहीदों की शौर्य गाथा को संजोने का कार्य सराहनीय है। चित्रों के माध्यम से नागरिक अपने गौरवशाली इतिहास को जान सकेंगे और बच्चे उनसे देशभक्ति की प्रेरणा ले सकेंगे। कुंवर चैन सिंह ने देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 24 जुलाई 1858 को युद्ध का आगाज कर सशस्त्र क्रांति की मशाल जलाई थी। नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पेंटिंग के माध्यम से शहीद कुंवर चैन सिंह और उनके विश्वस्त साथी हिम्मत खां, बहादुर खां को युद्ध के दृश्यों के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। टाउन के हाल के पास टीन की चादर पर श्रृंखलाबद्ध चित्र राहगीरों को न केवल आकर्षित करते हैं, बल्कि रुक कर जानने की जिज्ञासा पैदा करते हैं। नागरिकों द्वारा नगर पालिका के इस कार्य की सराहना की जा रही है।

रोजगार-स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला 11 मार्च को

सीहोर (निप्र)। शासन के निर्देशानुसार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 11 मार्च 2025 को सीहोर स्थित डॉ अम्बेडकर शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रातः 11 बजे से 04 बजे तक युवा संगम के तहत रोजगार-स्वरोजगार एंव अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेला में रोजगार विभाग द्वारा स्थानीय, प्रदेश एवं अन्य राज्यों की कंपनियों को आमंत्रित कर युवाओं को रोजगार प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्वरोजगार विभागों के स्वरोजगार प्राप्त हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। रोजगार मेले में आईटीआई विभाग द्वारा युवाओं को अप्रेन्टिसशिप के लिये चयनित किया जायेगा।

खतरनाक स्थानों से हटाए गए होर्डिंग दोबारा लगे, जिम्मेदारों को सुध नहीं

शहर की सुंदरता को ग्रहण लगाने के साथ हादसों का कारण बन सकते है होर्डिंग्स और फ्लैक्स

संजय द्विवेदी, बैतूल। शहर में मनमाने ढंग से होर्डिंग-फ्लैक्स लगे है, जो न सिर्फ शहर की सुंदरता को ग्रहण लगा रहे है, बल्कि भविष्य में हादसों का कारण भी बन सकते है। हालांकि नगरपालिका ने लगभग 6 माह पहले शहर में खतरनाक होर्डिंग हटाने के लिए कार्रवाई की थी, लेकिन अब अधिकांश जगह हालात जस के तस हो गए है। बस स्टैंड पर जिन ऊंची जगहों से होर्डिंग हटाए गए थे, वहां दोबारा होर्डिंग लग गए हैं। हालात यह है कि सब्जी, चाट और चाय की दुकाने, इन होर्डिंग्स के नीचे लग रही है। यहां तक कि छोटे बच्चे भी होर्डिंग के नीचे खेलते हैं। ऐसे में इन्हें हटवाने की जरूरत है, लेकिन नगरपालिका प्रयास नहीं कर रही हैं। बस स्टैंड, कोठी बाजार, कमानी गेट, गौठाना, गंज और कारगिल चौक समेत अन्य भीड़ वाली जगहों पर लगे होर्डिंग्स गर्मी में चलने वाली तेज हवा से गिरकर लोगों को गंभीर रूप से घायल कर सकते है। दरअसल शहर में नियमों को ताक पर रखकर चौक-चौराहों और भवनों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स और फ्लेक्स लगाकर संस्थाएं अपना प्रचार-प्रसार कर रही है, तो वहीं जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देने के लिए राजनीतिक होल्डिंग की भी कमी नहीं है। खास बात यह है कि इन्हें

लगाने के लिए अधिकांश लोगों ने तो अनुमति तक नहीं ली है। जिससे नगरपालिका को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। ऊपर से होर्डिंस को देखकर लगता है कि जैसे यह अब गिरने ही वाला है। जिससे राहगीरों को भी खतरा बना हुआ है।

6 महीने पहले हटाए थे होर्डिंग- 6 महीने पहले शहर के बस स्टैंड, कोठी बाजार समेत अन्य क्षेत्रों में से खतरनाक होर्डिंग चिन्हित करके हटवाने की कार्रवाही की गई थी। बस स्टैंड क्षेत्र में सभी होर्डिंग, जो खतरनाक ढंग से लगाए गए थे, उन्हें हटाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा होर्डिंग लगने लगे और नपा द्वारा इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। वैसे शहर में होर्डिंग लगाने का ठेका नपा ने नए सिरे से देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए टैंडर भी हो चुके हैं। इस ठेके के लिए नपा की ओर से रखी गई शर्तें, शहर में चर्चा का विषय हैं। यंहा उल्लेखनीय है कि शहर की 90 लोकेशन पर होर्डिंग लगाने का तीन साल के लिए ठेका 22 लाख में दिया गया है। लेकिन इसमें भी इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि सभी लोकेशन पर एक जैसे ही रेट ठेकेदार को कैसे दे दिए। यह भी विचारणीय है कि सभी लोकेशन पर एक जैसी ही राशि कैसे हो सकती हैं।

बधाई, आयोजनों के बड़े-बड़े फ्लैक्स, होर्डिंग्स- शहर के चौराहों पर लोगों ने राजनीतिक, आयोजन और व्यवसायिक होर्डिंस बैनर लगा रखे हैं। इनमें से कई होर्डिंग्स राजनीतिक है, जो कई महीनों से लगे है। लेकिन इन्हें भी नहीं उतारा गया। जबकि बाजार और भीड़ वाले क्षेत्रों में लगे बड़े-बड़े होर्डिंग, फ्लैक्स गर्मी में खतरा बनते जा रहे है। लोगों का कहना है गर्मी का सीजन आने वाला है। ऐसे में तेज हवा, आंधी भी चलती है। यदि होर्डिंस टूटकर गिरे तो लोगों को चोटिल भी कर सकते है। किन्तु नगरपालिका होर्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों का आरोप है कि अधिकांश होर्डिंग्स अवैध रूप से लगाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। लेकिन नपा द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जबकि होर्डिंग्स, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर लगाने के लिए नगरपालिका से अनुमति लेनी होती है और इसका शुल्क भी अदा करना पड़ता है।

होर्डिंस के मामले में यह है हालात

(1) बस स्टैंड परिसर में दो-मंजिल की ऊंचाई पर खतरनाक होर्डिंग 5-6 महीने पहले तक लगे थे, मामला उछलने के बाद इन्हें हटवाया गया था, लेकिन अब यहां पर दोबारा होर्डिंग लगा दिए गए हैं।

(2) गौठाना में कमानी गेट के आगे स्टेट हाईवे-43 के बगल में दोनों ओर खतरनाक होर्डिंग लगे है। अधिकांश होर्डिंग झुक गए हैं, इनके नीचे बच्चे खेलते हैं।

(3) कोतवाली चौराहे पर भी होर्डिंग के नीचे ही दुकानें लगती हैं। इन दुकानों पर कभी भी होर्डिंग गिर सकते हैं।

(4) पीडब्ल्यूडी चौक से कारगिल चौक के बीच रोड पर भी पान ठेले और समोसे-कचौड़ी की दुकानें खतरनाक होर्डिंग के नीचे ही लगती हैं।

(5) स्टेडियम के गेटों के सामने भी चाट दुकानें और कपड़े की दुकानें खतरनाक होर्डिंग के नीचे लग रही हैं। यहां वाहन भी गेटों के सामने खड़े होते हैं।

(6) नपा ने 22 लाख में 90 लोकेशन पर होर्डिंग लगाने का तीन साल के लिए ठेका दिया है।

इनका कहना है -

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण अभी अधिकांश कर्मचारी करों की वसूली एवं अन्य आवश्यक कार्य में लगे है। इसलिए अभी शहर से होर्डिंग हटवाने की कार्रवाही रोक दी है। जो अवैध होर्डिंग की जानकारी मिली है, उन्हें जल्द ही हटाने की कार्रवाही की जायेगी।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नपा बैतूल

लगभग 3-4 माह पहले शहर की ऊंची जगहों एवं खतरनाक स्थानों से होर्डिंग हटवाने की कार्यवाही की गई थी, यदि वहां दोबारा होर्डिंग लग गए हैं तो जल्द ही हटवाएं जाएगें। शहर में 90 लोकेशन पर होर्डिंग लगवाने का ठेका 22 लाख रुपये में दिया गया है और इसके टेंडर भी हो चुके हैं। जल्द ही पीआईसी की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। इस बार लोकेशन के आधार पर ठेका न देकर ठेकेदार को सभी जगह एक ही रेट दिए गए हैं।

- ब्रजगोपाल परते, राजस्व निरीक्षक, नपा बैतूल

वनवासी कल्याण परिषद की एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन

बैतूल। पारधी जनजातीय समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए,राष्ट्र धर्म और संस्कृति को संरक्षित करने में उनके विशिष्ट योगदान एवं गौरवशाली इतिहास से सबको परिचित कराने एवं पारधी समाज की संस्कृति का संरक्षण संवर्धन व समग्र विकास पर चिंतन मनन करने हेतु वनवासी कल्याण परिषद मध्यभारत के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सोमवार को इटारसी रोड स्थित एक मैरिज लॉन में किया गया । आयोजन सफल रहा ।

कार्यशाला में वनवासी कल्याण परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रवीण डोलकें,राष्ट्रीय जनजातीय आयोग नईदिल्ली से प्रकाश भाऊ उईके,माननीय राज्यपाल के सलाहकार सदस्य व सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता विक्रांत कुमरे,पारधी विकास परिषद विदर्भ प्रांत के संयोजक आशीष कावरे,प्रांत संगठन मंत्री तिलकराज दाँगी प्रांत संयोजक अध्यन समूह मध्य भारत प्रांत नीरज जैन(घुमंतू कार्य), पारधी समाज बैतूल के ज़िला अध्यक्ष अलस्या पारधी,शासकीय योजना एवं दस्तावेज के प्रांत संयोजक सौरभ द्विवेदी,वनवासी कल्याण परिषद के ज़िलाअध्यक्ष महेश्वर भलावी,सचिव छोटू सिंह उईके, हितरक्षा कार्य प्रमुख नरेंद्र उईके ज़िला संगठन मंत्री संतोष यादव व युवा कार्य प्रमुख कपिल प्रधान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रवीण डोलकें ने अपने वक्तव्य में कहा पारधी जनजातीय समाज शमशेर सिंह पारधी जैसे क्रांतिकारी योद्धाओं के वंशज हैं,प्राचीन समय में सैनिक में रूप में राजाओ की सेना में रहकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए विधर्मीयो से युद्ध लड़ते थे,कालांतर में अंग्रेजों के समय में पारधी जनजातीय ने अंग्रेजो को सर्वाधिक परेशान किया,उनके वंशानुगत युद्ध कौशल से अनेक अंग्रेज काल के कपाल में समा गये । पारधी जनजातीय से परेशान होकर 1871 में अंग्रेजों ने ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट बना कर पारधी समाज को क्रिमिनल ट्राइब के रूप में घोषित कर दिया,तब से पारधी समाज निरंतर संघर्ष कर रहा हैं ।आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग उन्हें उसी दृष्टिकोण से देखता हैं,घुमंतू जनजातीय होने के कारण अनेक दस्तावेजो का अभाव होता है जिस कारण अनेक शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हों पाता हैं,समाज में शिक्षा व जागरूकता के अभाव के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं से समाज संघर्ष करता रहता हैं,अतः भारतीय समाज के सभी समर्थ व संवेदनाओ से परिपूर्ण मानव होने के नाते आज हम सभी की ज़िम्मेदारी बनती हैं कि पारधी जनजातीय को मुख्यधारा में लाने के लिए हम सभी कार्य करे,पारधी जनजातीय समाज का भी दायित्व हैं कि हम अपना हाथ बड़ाकर समाज के उत्थान में अपना योगदान दे,वनवासी कल्याण आश्रम इस भाव को लेकर चला हैं आप भी सभी इसमें सहभागी बने,प्रकाश भाऊ उईके व विक्रांत कुमरे द्वारा भीं पारधी समाज की समस्याओं पर चर्चा की गईं क़ानूनी विधिक सहायता व समाज के अधिकारो के संबंध में जागरूक किया गया ।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पारधी जनजातीय समाज सम्मिलित हुआ,जिसने अन्य ज़िले भोपाल खंडवा हरदा आदि की भी सहभागिता रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में पारधी जनजातीय समाज के विजय सोलंकी,अजय सोलंकी,इंकेश राजपूत मनीष राजपूत महाजन राजपूत सोनू सोलंकी सदागीर राजपूत विनुष विकी सोलंकी कृष्णा सोलंकी पटेल राजपूत व योगेश राजपूत का विशेष योगदान दिया ।

ग्वालियर शार्ट फिल्म फेस्टिवल में बैतूल की फिल्म बिटिया रानी चयनित

बैतूल। ग्वालियर में 7 और 8 मार्च को होने वाले 'ग्वालियर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2025' में बैतूल की फिल्म 'बिटिया रानी' का चयन हुआ है। 'बिटिया रानी' का निर्माण उत्तम दीक्षित फिल्म्स के बैनर तले किया गया है और इसे भारतीय चित्र साधना से संबद्ध 'सतपुड़ा चलचित्र समिति एवं विश्व संवाद केंद्र म.प्र.' द्वारा आयोजित फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। फिल्म 'बिटिया रानी' की निर्माता आशा दीक्षित हैं, जबकि निर्देशन और कहानी लेखन की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम दीक्षित ने निभाई है। फिल्म का संगीत अखिलेश जैन ने दिया है। कलाकारों की बात करें, तो इसमें श्रेया पिपले, संगीत अवस्थी, माधुरी साबले और पंकज सोनी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2025 एक प्रतिष्ठित मंच है, जहां देशभर की चुनिंदा शॉर्ट फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है। बैतूल की इस फिल्म का चयन होना शहर के लिए गर्व की बात है। 'बिटिया रानी' सामाजिक संदेश से भरपूर फिल्म है, जो बेटियों के संघर्ष और सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। फिल्म के निर्देशक उत्तम दीक्षित ने बताया कि यह फिल्म महिलाओं और बेटियों की स्थिति पर एक सशक्त संदेश देने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के फिल्म फेस्टिवल बेहद अहम भूमिका निभाते हैं।

2600 रूपये के समर्थन मूल्य पर अब 15 मार्च से उपार्जित किया जायेगा गेहूं

हरदा (निप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम् में 1 मार्च से तथा शेष संभाग में 17 मार्च से खरीदी के निर्णय में बदलाव करते हुये राज्य सरकार ने किसानों की मांग पर पूरे प्रदेश में एक साथ 15 मार्च से ही खरीदी करने का निर्णय लिया है। श्री राजपूत ने बताया कि वर्तमान में गेहूं की फसल कटाई पूर्ण नहीं होने तथा मंडियों में आ रहे गेहूं में समर्थन मूल्य उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित नमी के प्रतिशत से अधिक होने के कारण किसानों को असुविधा से बचाने यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। विगत वर्षों में भी समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन 15 मार्च के बाद ही प्रारम्भ किया जाता रहा है।

किसानों को मध्यप्रदेश सरकार देगी 175 रूपये बोनस : खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 2425 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली किसान हितैषी प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं उत्पादक किसानों के हित में बडा और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समर्थन मूल्य 2425 रूपये के अतिरिक्त 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा की गई है। श्री राजपूत ने बताया कि राज्य के किसानों से 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जायेगी। खाद्य मंत्री ने किसानों के हित में लिये गये इस बड़े निर्णय के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताते हुये इसे खेती को लाभ का धंधा बनाने की ओर सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का एक हिस्सा बताया है।

विदिशा जिले के 250 किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का माना आभार

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा गेहूं उपार्जन पर कृषकों को बोनस राशि दिये जाने की घोषणा के उपलक्ष्य में आज रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर किसानों का आभार प्रदर्शन आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में विदिशा जिले से चार बस एवं अन्य चार पहिया वाहनों द्वारा 250 किसान मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए के अतिरिक्त 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस एवं धान विक्रय पर भी प्रोत्साहन राशि दिये जाने पर सम्मिलित कृषकों द्वारा उक्त आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन किया गया है।

बुधनी में घायल कोबरा को मिला नया जीवन

सर्प मित्र ने अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर ने 7 टांके लगाकर बचाई जान

सीहोर(निप्र)। सीहोर जिले के बुधनी में एक घायल कोबरा सांप को सर्प मित्र की सूझबूझ से नया जीवन मिला है। नर्मदा घाट पर नगर परिषद के कर्मचारी सफाई कर रहे थे। तब कचरा एकत्रित करते समय कचरे के ढेर में बैठे कोबरा सांप को चोट लग गई। सूचना मिलते ही सर्प प्रेमी अशोक पारे मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोबरा से काफी खून बह रहा था। वे तुरंत घायल सांप को लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचे। डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक उपचार किया और 7 टांके लगाकर कोबरा की जान बचाई। फिलहाल कोबरा सांप अशोक पारे की देखरेख में है। स्वस्थ होने पर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कार्यालय में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत अशोक पारे को सांप संरक्षण का विशेष जुनून है। वे कहीं से भी सांप की सूचना मिलते ही तुरंत मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अब तक वे कई जहरीले सांपों से लोगों की जान बचा चुके हैं। पारे का कहना है कि सांपों का संरक्षण बहुत जरूरी है। भारत कृषि प्रधान देश है और सांप कीटों को नियंत्रित कर फसलों की रक्षा करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में चूहे फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बीमारियां फैला सकते हैं।

नन्ही रोशनी को मिला स्कूल में दाखिला

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के सांगाखेडा कलां निवासी देवीराम कीर और सरिता कीर की 06 वर्षीय पुत्री रोशनी अब शिक्षा से वंचित नहीं रहेगी। कलेक्टर सोनिया मीना के दिशा-निर्देशों के तहत रोशनी को अब प्राथमिक विद्यालय में दाखिला मिलेगा और वह नियमित रूप से स्कूल जाएगी। मौका था प्रति मंगलवार आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम का जब सरिता कीर ने जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करते हुए अपनी बेटी के स्कूल में दाखिले की मांग की। कलेक्टर के निर्देशानुसार डीपीसी डॉ. राजेश जायसवाल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रोशनी का दाखिला प्राथमिक शाला में करवा दिया गया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देशानुसार जिले में शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में ही कई नवाचारों को प्रारंभ किया गया है, तथा इस कार्यवाही से एक और बच्ची को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। रोशनी के माता-पिता ने कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।रोशनी की शिक्षा यात्रा की शुरुआत के साथ अब वह भी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग कर पाएगी और जीवन के नए अध्याय में कदम रखेगी।

27 साल से फरार वन अपराधी राजू पिपरिया से हुआ गिरफ्तार

बैतूल(निप्र)। अलग-अलग 18 मामलों में पिछले 27 सालों से वन अमले और पुलिस को चकमा दे रहे कुख्यात वन और अन्य मामले के अपराधी राजू वाडिवा को आखिरकार वन अमले की सक्रियता के कारण पकड़ लिया। मुखबिरों से मिली सूचना के बाद सीसीएफ वासु कनौजिया और उत्तर वनमंडल के डीएफओ नवीन गर्ग ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई। आईएफएस विनोद जाखड़ और सारनी रेंजर शारदेंदु नायक समेत वनकर्मियों एक टीम बनाकर पिपरिया में आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो आरोपी वन अमले के हत्थे आ गया। सूचना मिली थी आरोपी पिपरिया में है इसके बाद उसे पकड़ लिया। राजू वाडिवा 1997 से कई अपराधों में आरोपी होने के बावजूद वन अमले को चमका दे रहा था।

संक्षिप्त समाचार

ग्रामीणजन विद्युत से सुरक्षा हेतु सावधानियाँ जरूर बरतें

इन्दौर (निप्र)। अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में असावधानीवश विद्युत से कई बार अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। यह दुर्घटनाएं कई बार जान- माल का नुकसान भी कर देती हैं। इनसे बचने के लिए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीणजनों से सावधानी बरतने की अपील की है। कभी भी विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी न करें। क्योंकि ऐसा करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जरा भी असावधानी या छेड़खानी से बड़े-बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। इसलिए ऐसी लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है उन्हें ऑंधी तूफान या अन्य किसी कारण से टूटने वाले तारों को अकस्मात् छूने का प्रयास न करें। इस दौरान जरूरी होगा कि लाइन टूटने की सूचना तत्काल निकटस्थ बिजली कंपनी के अधिकारी को अथवा विद्युत कर्मचारी को दें। संभव हो तो किसी आदमी को उस जगह, अन्य यात्रियों को चेतावनी देने के लिये भी बिठा दें। किसानों को सलाह है कि वे खेतों खलिहानों में ऊॅंची-ऊंची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियां, झोपड़ी, मकान अथवा तंबू आदि विद्युत लाइनों के नीचे अथवा अत्यंत समीप न बनायें। साथ ही विद्युत लाइनों के नीचे से अनाज, भूसे आदि की ऊँची भरी हुई गाड़ियॉं न निकालें, इससे आग लगने एवं प्राण जाने का खतरा है। बहुत से स्थानों पर बच्चे पतंग अथवा लंगर का खेल खेलते तरह-तरह के धागे और डोर विद्युत लाइनों में फंसा देते हैं। ऐसा करने से उन्हें रोकें। लाइनों में फंसी पतंग निकालने के लिए बच्चों को कभी भी खंभे पर न चढ़ने दें। इससे एक ओर जहां दुर्घटना को टाला जा सकेगा वहीं दूसरी ओर आप होने वाली आर्थिक हानि से भी बच सकेंगे।

राज्य स्तरीय लोकोत्सव कार्यक्रम के संबंध में बैठक संपन्न

- **बेरछा मे प्रदेश के लोक कलाकारों का तीन दिवसीय लोकोत्सव का होगा आयोजन**

शाजापुर (निप्र)। नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं जिला प्रशासन शाजापुर द्वारा प्रदेश के लोक कलाकारों का राज्य स्तरीय लोकोत्सव का आयोजन बेरछा के लक्ष्मी मैरिज गार्डन बेरछा में किया जा रहा है। उक्त आयोजन के संबंध में आज कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संतोष टैगोर ने बेरछा में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यक्रम की तैयारी के लिएआवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने की जाने वाली तैयारी का जायजा भी लिया। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री शिवम यादव, संयुक्त कलेक्टर व प्रभारी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे। प्रभारी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकोत्सव अंतर्गत प्रदेश की समृद्ध लोक कला, लोकनृत्य, लोक गीत, लोकनाट्य का प्रदर्शन प्रदेश से आ रहे 250 से अधिक शासकीय एवं अशासकीय कलाकारों द्वारा प्रतिदिन सायं 7.00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक किया जाएगा। कार्यक्रम में नशा मुक्ति के संदेश के साथ-साथ दर्शक प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत, कबीर भजन, मालवी लोक नृत्य, बधाई लोकनृत्य, गीड़ी लोक नृत्य, भगोरिया लोक नृत्य, गुदुम्ब वादन लोक नृत्य, आदि का प्रदर्शन देख सकेंगे। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कलापथक कोरल ग्रुप द्वारा नशामुक्ति एवं विभागीय योजना गीतों एवं नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी। प्रथम दिवस कोरल ग्रुप द्वारा सरस्वती वंदना, नशाबंदी लोकगीत, कबीर भजन मंडल शाजापुर द्वारा कबीर भजन, गुदुम्ब वादन लोक नृत्य अशासकीय कला मंडल डिंडोरी द्वारा गुदुम्ब वादन लोकनृत्य, जन चौपाल समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा लोक नृत्य राई, नवयुवक मंडल बेगमगंज द्वारा लोकगीतों की प्रस्तुति एवं वीर तेजाजी लोक कला मंडल थांदला झाबुआ द्वारा आदिवासी लोक नृत्य भगोरिया की प्रस्तुति दी जाएगी

होम्योपैथी महाकुंभ-2025, इनोवेशन इन होम्योपैथी पर हुई बात

जीएसआईटीएस में अगले वर्ष से बायोटेक्नोलॉजी के साथ होम्योपैथी पढ़ाई जाएगी : नितेश पुरोहित

एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर द्वारा 11वीं नेशनल कॉफ्रेंस संपन्न,होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आयुष रत्न और आयुष मित्र से चिकित्सकों को किया गया अलंकृत

इन्दौर (निप्र)। कम्युनिटी हेल्थ एवं वेलफेयर के अंतर्गत भारत सरकार के एनीमिया मुक्त अभियान के तत्वावधान में एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर द्वारा एनीमिया जागरूकता रथ सप्ताह का समापन होम्योपैथी महाकुंभ-2025 - 11वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रविवार को हुआ। 11वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनोवेशन इन होम्योपैथी पर विस्तार से बात की गई। देश के अलग अलग हिस्सों से आए डॉक्टर्स ने होम्योपैथी की सहायता व अपनी प्रेक्टिस और रीसर्च के माध्यम किए जा रहे उपचार के बारे में बताया। साथ ही वर्तमान दौर में चिकित्सा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की मदद लेने की बात कही। इसके अलावा जीएसआईटीएस कॉलेज में शुरू किए गए बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में होम्योपैथी चिकित्सा को भी शामिल किए जाने की पहल करने का निर्णय लिया गया। मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी थे।

विशिष्ट अतिथि जीएसआईटीएस कॉलेज के डायरेक्टर श्री नितेश पुरोहित,आईएम इंदौर के अध्यक्ष डॉ.नरेंद्र पाटीदार,शिवांग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल के प्राचार्य डॉ.डी.एन. मिश्रा एवं सेम्स इंदौर के रजिस्ट्रार डॉ आनंद मिश्रा थे। सांसद श्री लालवानी ने कहा रिसर्च के माध्यम से कई गंभीर बीमारियों का इलाज होम्योपैथी के माध्यम से किया जा रहा है। भारत सरकार सिकल सेल बीमारी को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसमें हमें भी प्रयास करना होंगे। इसके अलावा शादी से पहले ब्लड ग्रुप के मिलान की जरूरत है। इसके लिए मैंने संसद में भी अपनी बात रखी है। जीएसआईटीएस कॉलेज के डायरेक्टर श्री पुरोहित ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है ऐसे में मेडिकल फील्ड को इससे जोड़ा जाना चाहिए ताकि दोनों की मदद से मरीजों को बेहतर उपचार दिया जा सके। श्री पुरोहित ने कॉलेज में शुरू किए गए बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में होम्योपैथी विषय को भी जोड़ने की पहल करने की बात रखी और आयुष मंत्रालय,भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार मंडल (सीसीआरएच) के सदस्य और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद सदस्य तथा एडवांस्ड होम्यो-हेल्थ सेंटर एवं होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्रा.लि.के संचालक डॉ.ए.के. द्विवेदी से कॉन्फ्रेंस के डिटेल्स के साथ इस पर काम करने का निवेदन किया। साथ ही कॉन्फ्रेंस में इनोवेशन इन होम्योपैथी और टेक्नोलॉजी विषय को भी शामिल करने पर सराहना की। डॉ.ए.के. द्विवेदी ने कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। डॉ. द्विवेदी ने हेमेटोहाइड्रोसिस (खूनी पसीना) विषय पर अपनी बात रखी। साथ ही होम्योपैथी दवाओं से दिए उपचार के केस की जानकारी भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। डॉ.नैना टेमले एमडी पीडियाट्रिक्स स्कॉलर शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल ने डिस्लेस्किया विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने ब्लाइंड हैंडीकैप यानि न दिखने वाला हैंडीकैप के बारे में बताया। कहा कि इसमें बच्चों को पढ़ने और समझने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर डॉ. टेमले ने डिस्लेस्किया के केस भी प्रस्तुत किए। डॉ.जयेश पटेल नेशनल स्पीकर एवं सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन सूरत ने कैंसर एंड होम्योपैथी विषय पर कहा कि ह्यूमन बॉडी में क्क3 एन्टी जीन्स होता है जो कैंसर सेल को बढ़ने नहीं देता। प्रोग्राम में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए डॉक्टर्स व अन्य को आयुष रत्न और आयुष मित्र से अलंकृत किया गया। साथ ही सभी वक्ताओं व अथितियों को अनार के पौधे,भगवत गीता भेंट की गई।

कार्यक्रम में श्री दीपक उपाध्याय, डॉ.जितेंद्र पूरी, डॉ.विवेक शर्मा, डॉ.विनय पांडे,कैंसर एंड होम्योपैथी विषय पर वक्ता डॉ. जयेश पटेल, रिसर्च ऑन सिकल सेल डिसिस एंड होम्योपैथी पर डॉ.रेणु मित्तल, रोल ऑफ होम्योपैथी इन ऑटिज्म पर वक्ता डॉ.समीर चौकर,हीमोग्लोबिनोपैथी एंड एचपीएलसी पर डॉ.संगीता पानेरी,सेल्फ एक्सपीरिएंस ऑफ होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशियेंसी एनीमिया पर डॉ.उषा जैन, इनर थॉअट्स एंड इमोशन ऑफ पीपुल सफरिंग फ्रॉम कॉम्पलेक्स एंड सिरियस इलनेस पर डॉ.वैभव चतुर्वेदी,विजन ऑफ इमपॉसिबल टू पॉसिबल बाय होम्योपैथी पर डॉ.अर्पित चौपड़ा जैन, डॉ.नैना टेमले,डॉ.जयश्री राठवां, होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया एंड हेमोटोहाइड्रोसिस पर डॉ.ए.के.द्विवेदी ने अपने विचार व्यक्त किये।

शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियो की खेल प्रतियोगिता का समापन

शाजापुर (निप्र)। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन शाजापुर द्वारा आयोजित की जा रही शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियो की कबड्डी, क्रिकेट एवं बैडमिंटन की खेल प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। कबड्डी में प्रथम जिला शिक्षा विभाग की टीम रही, द्वितीय खेल और युवा कल्याण विभाग एवं तृतीय उच्च शिक्षा विभाग की टीम रही। बैडमिंटन सिंगल में प्रथम श्री दिनेश धनगर, द्वितीय श्री गोविन्द पारिहार एवं तृतीय श्री रामप्रसाद समरावत रहे। इसी प्रकार बैडमिंटन डबल्स में श्री सूरज जाट, श्री दिनेश धनगर उच्च शिक्षा विभाग प्रथम, श्री रामप्रसाद समरावत, श्री आशय श्रीवास्तव राजस्व विभाग द्वितीय स्थान एवं श्री सौरभ सिंह चौहान, श्री शाहनवाज खान पुलिस विभाग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। क्रिकेट में प्रथम स्थान राजस्व विभाग, द्वितीय स्थान पुलिस विभाग एवं तृतीय स्थान ऊर्जा विभाग की टीम ने प्राप्त किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक श्री अरूण भीमावद, कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना, पुलिस अधीक्षक श्री यशपालसिंह राजपूत एवं अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर सुश्री मनीषा वास्कले द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त टीमो को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया।

बिजली कंपनी के एमडी श्री सिंह ने अधिकारियों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आपूर्ति व्यवस्था देखी

इन्दौर (निप्र)। म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उच्च स्तरीय दल ने रविवार को प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा किया। दल में कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह, निदेशक तकनीकी श्री सचिन तालेवार, अधीक्षण यंत्री श्री सी.ए. ठकार, कार्यपालन यंत्री श्री जयेंद्र ठाकुर शामिल थे। दल ने प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में अतिउच्च दाब लाइन, उच्च दाब लाइन, निम्न दाब लाइन का नेटवर्क अत्याधुनिक तरीके से किस तरह स्थापित किया जाए, इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त की। महाकुंभ क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति शिकायत निवारण संबंधित सिस्टम का बारीकी से अवलोकन किया गया। खुले क्षेत्र में सुरक्षित तरीके से बिजली आपूर्ति व्यवस्था संचालन संबंधी जानकारी बिंदुवार प्राप्त की। पश्चिम क्षेत्र के दल को प्रयागराज स्थित पूर्वांचल बिजली वितरण निगम के वरिष्ठ अभियंता श्री मनोज गुप्ता ने महाकुंभ मेला क्षेत्र, कंट्रोल सेंटर व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण कराया। पश्चिम क्षेत्र के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने कहा कि यह दौरा उज्जैन के सिंहस्थ 2028 कुंभ के लिए उपयोगी रहेगा।

चिमनी से उत्सर्जित पैरामीटर की मात्रा निर्धारित मानक सीमा के भीतर

निर्धारित एसओपी के अनुसार किया जा रहा है यूनियन कार्बाइड के अपशिष्ट का डिस्पोजल

इन्दौर (निप्र)। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2802/2004 (आलोक प्रताप सिंह विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में विगत 18 फरवरी 2025 को पारित आदेशानुसार यूनियन कार्बाइड के अपशिष्ट का प्रथम ट्रायल रन 27 फरवरी 2025 से मेसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रीयल वेस्ट मैनेजमेंट प्रा.लि. पीथमपुर, जिला धार द्वारा संचालित इंसीनरेटर में किया जा रहा है। संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने बताया कि यूनियन कार्बाइड की फीडिंग 28 फरवरी 2025 को अपरान्ह 3 बजे से 135 किलोग्राम/घण्टे की दर से की जा रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार अपशिष्ट का डिस्पोजल कराया जा रहा है। डिस्पोजल के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग एवं निगरानी का कार्य किया जा रहा है। संभागायुक्त श्री सिंह ने बताया कि आज एक मार्च 2025 को अपरान्ह 3 बजे तक 3 हजार 240 किलोग्राम अपशिष्ट का दहन किया जा चुका है। अपशिष्ट के साथ लगभग 3 हजार 240 किलोग्राम लाईम भी मिलाकर दहन किया गया है। फ्लू गैसेस की सफाई हेतु लगभग 3.6 टन लाईम, 1.8 टन एक्टीवेटेड कार्बन तथा 24 किलोग्राम सल्फर का उपयोग किया गया। अपशिष्ट दहन हेतु लगभग 400 से 500 प्रति घण्टे डीजल की खपत हो रही है। अपरान्ह तीन बजे तक लगभग 21 हजार लीटर की खपत हो चुकी है। अपशिष्ट के दहन के दौरान चिमनी से हो रहे इमीशन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके लिये ऑनलाईन कन्टीन्युअस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित है। चिमनी से उत्सर्जित पैरामीटर की मात्रा निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये जा रहे है।

निर्धारित अधिकतम मानक सीमा से भीतर हो रहा है चिमनी से उत्सर्जन : संभागायुक्त श्री सिंह ने बताया कि चिमनी से उत्सर्जित पैरामीटर की मात्रा निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाये जा रहे है। पर्टीक्यूरेट मेटर का उत्सर्जन 8.6 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है, जिसकी निर्धारित अधिकतम मानक सीमा 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है। इसी तरह सल्फर डाईऑक्साइड का उत्सर्जन 62 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है, इसकी अधिकतम मानक सीमा 200 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है। नाईट्रोजन ऑक्साईड्स का उत्सर्जन 52.5 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है, इसकी निर्धारित अधिकतम मानक सीमा 400 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है। कार्बन मोनो ऑक्साईड का उत्सर्जन 10 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है, इसकी अधिकतम मानक सीमा 100 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर है।

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम ने रुकवाया बाल विवाह

खण्डवा (निप्र)। चाईल्ड लाईन के माध्यम से बाल विवाह संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा शनिवार को तत्काल कार्यवाही की गई एवं बाल विवाह रूकवाया गया। परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास छैगांवमाखन श्री नंदराम चौहान ने बताया कि ग्राम लखनगांव के सामरबाबा मंदिर में ग्राम बांगरदा का लड़का एवं ग्राम जिनवानिया की लड़की के बाल विवाह संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसकी जाँच करने पर लडकी की आयु 18 वर्ष से कम पाई गई। टीम द्वारा विवाह को रूकवाते हुए लड़का एवं लड़की के परिवारों को बाल विवाह से संबंधित दुष्परिणाम एवं कानूनी कार्यवाही से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह कराये जाने पर बाल विवाह में सम्मिलित समस्त लोगों जैसे पण्डित, बाराती, बेण्डवाले, हलवाई, टेंट वाले एवं अन्य समस्त जो विवाह में सम्मिलित थे, उन पर बाल विवाह संबंधी धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इसके लिए सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है । परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास छैगांवमाखन श्री चौहान ने बताया कि समझाईश देने पर दोनों परिवारों के सदस्यों द्वारा विवाह कार्यक्रम को रद्द करते हुए लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह किये जाने की लिखित सहमति प्रदाय की गई । कार्यवाही के दौरान सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती कांता कांचले, आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका एवं पुलिस विभाग की टीम तथा ग्राम के सरपंच उपस्थित रहे ।

आयुष्मान भारत योजना की मदद से सोनू का हुआ सफल ऑपरेशन

खण्डवा (निप्र)। गर्भावस्था के नवें महीने में प्रसव पीड़ा के अवस्था में सोनू पति गजेंद्र मालवी निवासी कुसुमकोट तहसील धारनी जिला अमरावती को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धारनी में लेकर गये थे द्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला की जाँच करने पर पाया गया कि वह गंभीर एनीमिक एवं अन्य हाईरिस्क कंडीशन होने के कारण 24 फरवरी को श्री दादाजी धूनीवाले जिला चिकित्सालय सह नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में लेकर आए थे द्य सोनू को डॉ. लक्ष्मी डूडवे स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा देखा एवं तत्काल अन्य आवश्यक जाँचे करवाई, जिसमें पाया गया कि महिला गंभीर एनीमिक है द्य स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. लक्ष्मी डूडवे ने बताया कि महिला का ब्लड ग्रुप आर.एच. नेगेटिव होने के कारण कहीं भी ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी।

काफी मशक्कत के बाद आर.एच. नेगेटिव वाले रक्तदाता का पता लगाकर उसे घर से बुलवाकर ब्लड की व्यवस्था की। सोनू को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर डॉ. लक्ष्मी डूडवे स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं डॉ. रसना स्त्री रोग विशेषज्ञ व उनकी पूरी टीम द्वारा 24 फरवरी को सफल ऑपरेशन किया और उनके बेटे ने जन्म लिया। बच्चे का वजन 2 किलो 700 ग्राम है और पूरी तरह से स्वस्थ है । स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. लक्ष्मी डूडवे द्वारा बताया गया कि जब मरीज को जिला चिकित्सालय में लेकर आए थे, उस समय महिला की स्थिति गंभीर थी। ऐसी गंभीर स्थिति में मरीज को बचाना चुनौती पूर्ण कार्य डॉक्टर के लिए होता है द्य मरीज के लिए तत्काल खून की व्यवस्था कर 3 यूनिट रक्त चढ़ाकर महिला की जान बचाई गई द्य उन्होंने बताया कि जच्चा बच्चा अभी दोनों स्वस्थ हैं और 28 फरवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है द्य पति गजेंद्र द्वारा बताया गया जब मैं अस्पताल लेकर आया था तब मेरी पत्नी की हालत बहुत गंभीर थी। मैं उसे सीरियस अवस्था में यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर डॉ. लक्ष्मी डूडवे स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं डॉ. रसना स्त्री रोग विशेषज्ञ व उनकी पूरी टीम द्वारा समय पर उपचार दिया । इसके कारण मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान बची। गजेंद्र ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी सुविधा निःशुल्क प्राप्त हुई हैं द्य गजेंद्र ने जिला चिकित्सालय में इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध होने के लिए सरकार, जिला प्रशासन एवं अस्पताल चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया।

लोक अदालत और मध्यस्थता के संबंध में जनजागृति के लिये निकली विशाल मैराथन

बच्चों से लेकर बुजुर्गों सहित न्यायाधिपति,अधिवक्ता,अधिकारियों,नागरिकों ने लिया हिस्सा

इन्दौर (निप्र)। इंदौर में आज रविवार को लोक अदालत और मध्यस्थता के संबंध में जनजागृति के लिये विशाल मैराथन निकाली गयी। इस विशाल मैराथन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों सहित न्यायाधिपति, अधिवक्ता, अधिकारियों, नागरिकों आदि ने हिस्सा लिया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के कैंपस में यह मैराथन सुबह पंजीयन के साथ प्रारंभ हुई। मैराथन का शुभारंभ झण्डी दिखाकर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री संजीव सचदेवा एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर के अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया ने किया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधिपति भी विशेष रूप से मौजूद थे। मैराथन में भाग लेने हेतु एक हजार 205 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मैराथन एवं जागरूकता रैली में लगभग एक हजार 500 से अधिक प्रतिभागी सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों को कैप एवं टी-शर्ट दिये गये। मैराथन सुबह 07:30 बजे हाई कोर्ट कैंपस से प्रारंभ होकर जंजीरवाला चौराहा, इण्डस्ट्री हाउस, पलासिया, गीता भवन चौराहा, मधु मिलन चौराहा होते हुए रीगल चौराहा से उच्च न्यायालय के गेट क्रमांक एक हाई कोर्ट कैंपस में सम्पन्न हुई।

न्यायाधिपति श्री संजीव सचदेवा द्वारा बताया गया कि आज की जागरूकता मैराथन एवं रैली में उपस्थित जन सैलाब को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सभी मध्यस्थता के माध्यम से समाजिक रिश्तों में समरसता लाने का भरपूर प्रयास कर रहे है। आप लोगों को देखकर हमारा उत्साह बढा है । आप लोग जिस पथ पर चल रहे है वह अविस्मरणीय है। यहां उपस्थित दो साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग का हौसला देखकर मुझे यकीन है कि आप लोग मध्यस्थता के मार्ग में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे।

न्यायाधिपति द्वारा वकालत के दिनों की कहानी सुनाते हुए बताया गया कि मां-बेटे के बीच का विवाद गुरुद्वारा के समक्ष पहुंचा जहां पर बेटे को बताया गया कि मां के पैर छू लो, मां के चरणों में तो स्वर्ग होता है, बेटे के पैर छूते ही मां ने उसे गले लगाया और विवाद का वहीं निराकरण हो गया। न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया द्वारा बताया गया कि लोक अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का निराकरण होने से विन-विन (न कोई जीता न कोई हारा) की स्थिति होती है इसमें दोनों पक्षकार की विजय होती है। इन्दौर में सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से लगभग पाँच हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया जा चुका है। जिस कारण लगभग पाँच हजार से अधिक प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया से बच गए हैं। इसमें 27 समाज के 110 मध्यस्थतों की अहम भूमिका है। मध्यस्थता के कार्य को न केवल प्रत्येक समुदाय द्वारा अपितु रेवन्यू विभाग की जनसुनवाई, पुलिस कमिश्नर जनसुनवाई में भी किया जा रहा है। इसके साथ ही भविष्य में नगर निगम के जनसेवा केन्द्र (कम्युनिटी हॉल) के माध्यम से भी मध्यस्थता कार्यवाही संचालित की जाएगी। न्यायाधिपतिगण द्वारा विजेताओं को मेडल एवं प्रथम पुरस्कार 11 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 7 हजार 100 रूपये एवं तृतीय पुरस्कार 5 हजार 100 रूपये पुरस्कार क्रमशः पुरूष वर्ग में श्री वंश चौधरी, श्री संजय मुकाती तथा श्री जयंत नास्कर तथा महिला वर्ग में सुश्री प्राची पड़ियार, सुश्री जयश्री राय तथा सुश्री पलक सोनकर को प्रदान किये गये। मैराथन में उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के न्यायाधिपति श्री सुबोध अभ्यंकर, न्यायाधिपति श्री प्रेम नारायण सिंह,न्यायाधिपति श्री बी.के. द्विवेदी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इन्दौर, ओ.एस.डी. रजिस्ट्रार म.प्र. उच्च न्यायालय खण्पीठ इन्दौर, जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण,महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, संभागायुक्त श्री दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री शिवम वर्मा के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण, उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के साथ सामुदायिक मध्यस्थ चैनल अधिवक्तागण, डॉ.मोहम्मद शमीम सेवा निवृत्त न्यायाधीश मॉस्टर ट्रेनर उपस्थित रहे।

॥ मंदिरम् ॥

50

कुक्कुटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश

कुक्कुटेश्वर मंदिर जिसे पीठापुरम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के पीतापुरम में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर शैव और शाक्त हिंदू परंपराओं दोनों में महत्वपूर्ण है। यह अठारह महा शक्तिपीठों में से एक है, जिन्हें शक्तिवाद में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माना जाता है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान कुक्कुटेश्वर हैं, जो भगवान शिव का मुर्गे जैसा रूप है, और उनकी पत्नी राजराजेश्वरी देवी हैं। पुरुहुतिका देवी मंदिर, महा शक्तिपीठों में से एक, कुक्कुटेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित है। पीठापुरम का उल्लेख स्कंद पुराण में, श्रीनाथ के भीमेश्वर पुराणमु में और समुद्रगुप्त द्वारा इलाहाबाद में एक पत्थर के स्तंभ पर किया गया है। कुक्कुटेश्वर स्वामी एक स्पतिका लिंगम स्वयंभू हैं। यह मंदिर अपने एक पत्थर वाले नंदी के लिए भी प्रसिद्ध है।

खंडवा के नजरपुरा आईलैंड में बनेंगे लग्जरी रिसॉर्ट

इंदौर का ट्रेजर ग्रुप इन्वेस्ट करेगा, खजुराहो-सांची में भी डेवलप करने का प्लान

भोपाल। खंडवा के नजरपुरा आइलैंड में लग्जरी रिसॉर्ट बनेंगे। इंदौर का ट्रेजर ग्रुप यहां इन्वेस्ट करेगा। खजुराहो-सांची में भी गोल्फ कोर्ट और रिसॉर्ट बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। अगले 5 साल में निवेश का प्लान है। भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ट्रेजर ग्रुप ने निवेश के लिए यह प्रस्ताव दिए। एमपी पर्यटन विकास निगम ने इसे लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी है।

नजरपुरा आइलैंड खंडवा: इंदिरा सागर डैम के बैक वाटर एरिये में ये आइलैंड है। यहां पर 17.57 हेक्टेयर भूमि पर 138.34 करोड़ रुपए से 106 लग्जरी रूम, 2 रेस्टोरेंट, वॉटर स्पोर्ट्स, विश्व स्तरीय वेलनेस रिसॉर्ट (स्पा, मेडटेशन-योगा) एवं अन्य एक्टिविटी होग और 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सांची में रिसॉर्ट- सांची के पास नीनोद में 77 हेक्टेयर जमीन पर कुल 246.02 करोड़ रुपए की लागत से 217 लग्जरी रूम एवं विलाज, 5 रेस्टोरेंट, गोल्फ कोर्ट, गोल्फ विला, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस सेंटर एवं टूरिज्म से जुड़ी अन्य एक्टिविटी होगी। इससे करीब साढ़े 6 सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। खजुराहो में गोल्फ कोर्ट- खजुराहो स्थित दतला पहाड़ में 72.943 हेक्टेयर जमीन पर 206.27 करोड़ रुपए की लागत से 204 लग्जरी स्वीट रूम्स, 2 रेस्टोरेंट, गोल्फ कोर्ट, वेलनेस सेंटर, थीम गार्डन, हेरिटेज वॉल, हॉट एयर बैलूनिंग जैसी पर्यटन सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसमें 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ट्रेजर ग्रुप इंदौर का है। ग्रुप के यहां पर कई प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी रियल एस्टेट विकास, पैकेजिंग उत्पादों के निर्माण, पवन ऊर्जा उत्पादन, हर्बल उत्पादों समेत अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। ग्रुप ने तीनों ही जगहों पर 600 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया है।

जीआईएस-भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ हुए एमओयू

युवाओं और उद्योगों के बीच की दूरी अब होगी कम: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-भोपाल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड-शो के परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बना। साथ ही कुशल मैन पॉवर उपलब्ध कराने वाला आदर्श स्थान पर बन गया है। प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट को आपस में जोड़ते हुए 'इंडस्ट्री-रेडी वर्क फोर्स' तैयार करने की दिशा में कई रणनीतिक साझेदारियां की हैं। इससे लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जीआईएस-भोपाल में कौशल विभाग ने कई देशी-विदेशी एजेंसियों के साथ एमओयू किये। ये एजेंसियां आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए एडवांस ट्रेड्स एवं विधाओं का कौशल प्रशिक्षण देंगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेशकों को कुशल वर्क फोर्स मिलेगा। जीआईएस में युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 8 एमओयू साइन किये गये। इंडो-जर्मन ग्रीन स्किल्स (जीआईजेड) और कंपनी श्नाइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में सिमुलेशन-बेस्ड ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। इससे इलेक्ट्रिशियन और सोलर तकनीशियन जैसे ट्रेड्स में कुशल युवाओं की मांग पूरी होगी। इसी प्रकार, जीआईजेड और सिमेंस इंडिया की साझेदारी आईटी प्रशिक्षुओं को इंडस्ट्री-रेडी ग्रीन स्किल्स प्रदान करेगी। इससे प्रदेश में सतत् और समावेशी व्यावसायिक कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। साइन्टेक टेक्नोलॉजीज और अपनाटाइम टेक प्रा. लि. के साथ मिलकर ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और अपस्किलिंग की पहल की जा रही है। इससे इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिभा को विकसित किया जा सकेगा। यह कंपनी अपने डिजिटल भर्ती प्लेटफॉर्म से प्रदेश के युवाओं को संभावित नियोक्ताओं से जोड़ेगी, इससे रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और व्यापक होगी। ग्वालियर के सरकारी डिविजनल आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के प्रशिक्षुओं को मार्तंडक सोलर एनर्जी प्रा. लि. द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रायोजित किया जाएगा। इससे तकनीकी शिक्षा और उद्योग की मांग के बीच संतुलन स्थापित होगा। उन्नति फाउंडेशन स्वयम पोर्टल के माध्यम से रोजगार उन्मुख ऑनलाइन पाठ्यक्रम, साइकोमेट्रिक विश्लेषण और कैरियर गाइडेंस प्रदान कर रही है, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। प्रदेश के युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के लिए वन वर्ल्ड एलायंस जापान के सहयोग से जापानी भाषा और आवश्यक कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे जापान में भी रोजगार के लिए तैयार हो सकेंगे।

इंडस्ट्री-रेडी आईटी प्रशिक्षुओं के लिए ग्रीन स्किल्स-जीआईजेड और सिमेंस इंडिया के सहयोग से, मध्यप्रदेश में आईटी प्रशिक्षुओं को इंडस्ट्री-प्रासंगिक ग्रीन स्किल्स से लैस करने, जेंडर समावेशन को बढ़ावा देने और वर्क-रेडीनेस को सशक्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह सहयोग प्रदेश में सतत और समावेशी व्यावसायिक कार्यक्रमों को मजबूत करेगा।

जीआईएस भोपाल से मिलेगा रोजगार अवसरों को नया आयाम

मध्यप्रदेश में ग्रीन स्किल्स और इंडस्ट्री-रेडी वर्क फोर्स को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय सहयोग जीआईएस-भोपाल के प्रभावी परिणामों के रूप में, मध्यप्रदेश में कौशल विकास और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किए गए हैं। इंडस्ट्री-फोकस्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण साझेदारियों को मूर्त रूप दिया गया है। इंडो-जर्मन ग्रीन स्किल्स (जीआईजेड) और कंपनी श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने 'सिमुलेशन-बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर ग्रीन एनर्जी जॉब्स' (ग्रीन स्किल्स) परियोजना के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिशियन और सोलर तकनीशियन ट्रेड के व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए एसएसआर ग्लोबल स्किल पार्क और कौशल विकास निदेशालय के साथ समझौता किया है।

इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी शिक्षा

मार्तंडक सोलर एनर्जी प्रा. लि. द्वारा ग्वालियर के सरकारी डिविजनल आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के प्रशिक्षुओं को प्रायोजित किया जाएगा, इससे तकनीकी शिक्षा और उद्योग आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटा जा सकेगा। साथ ही युवाओं की एम्प्लोयबिलिटी को बढ़ाया जा सकेगा। युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) और साइकोमेट्रिक विश्लेषण को मजबूत करने के लिए उन्नति फाउंडेशन द्वारा स्वयम प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश की गई है। इसके साथ ही, मध्यप्रदेश सरकार के उद्योगम पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसरों को सुलभ बनाया जाएगा। वन वर्ल्ड एलायंस जापान के सहयोग से, मध्यप्रदेश के छात्रों को जापानी भाषा और आवश्यक कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे जापान में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार हो सकें। यह पहल राज्य के युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।

जीआईएस से रोजगार में आएगा बड़ा बदलाव- जीआईएस-भोपाल के बाद मध्यप्रदेश ने कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय साझेदारियों को मूर्त रूप दिया है। इन समझौतों से युवाओं को उद्योग-रेडी बनाया जा रहा है। साथ ही तकनीकी शिक्षा को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुरूप उन्नत किया जा रहा है। इन सहयोगों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को ग्रीन एनर्जी, आईटी, तकनीकी और वैश्विक रोजगार के क्षेत्रों में नए अवसर प्राप्त होंगे। जीआईएस-भोपाल से निवेश भी आकर्षित हुआ है और लाखों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

सायंटेक टेक्नोलॉजीज और अपना टाइम टेक प्रा. लि. के साथ साझेदारी के तहत, छात्रों को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग, अपस्किलिंग और इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार के लिए तैयार करने की पहल की गई है। अपना डिजिटल भर्ती मार्केटप्लेस के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को संभावित नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया जा रहा है।

कान्हा पार्क में बारह दिन में दूसरी बार मिला बाघ का शव

- जबड़ा टूटने से मौत, पोस्टमार्टम ने खोला चौंकाने वाला राज

भोपाल। कान्हा नेशनल पार्क से एक दुखद खबर आई है। सूपखार क्षेत्र में एक बाघ की मौत हो गई। यह मौत बाघों के बीच हुए खूनी संघर्ष का नतीजा है। वन विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, बाघ के जबड़े की हड्डी टूटने से उसकी मौत हुई। यह घटना लगभग 4-5 साल के युवा बाघ के साथ हुई। यह 12 दिनों के अंदर दूसरी बाघ मृत्यु है, जिससे वन विभाग में चिंता बढ़ गई है वन विभाग की टीम गश्त कर रही थी, तभी उन्हें मृत बाघ दिखाई दिया। तुरंत ही एनटीसी, दिल्ली और मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक के कार्यालय को सूचित किया गया। उनके निर्देशों के अनुसार, घटनास्थल को सुरक्षित किया गया और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू की गई। यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि बाघ की मौत किसी शिकारी की वजह से तो नहीं हुई। बाघ का पोस्टमार्टम वन्यजीव चिकित्सक डॉ. संदीप अग्रवाल और डॉ. राकेश वारेश्वा ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला

कि बाघ के सभी अंग सुरक्षित थे, लेकिन उसके जबड़े की हड्डी बुरी तरह टूटी हुई थी। इससे साफ हो गया कि बाघ की मौत आपसी लड़ाई में हुई है। मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद, बाघ का अंतिम संस्कार नियमानुसार कर दिया गया। बाघ के अंतिम संस्कार के दौरान क्षेत्र संचालक रवीन्द्रमणि त्रिपाठी, उपसंचालक पुनीत गोयल, सहायक संचालक मुकेश कुमार जामोर, जे.सी. भगत तहसीलदार बैहर, परशुराम चौहान एनटीसी प्रतिनिधि, चन्द्रेश खरे वन्यप्राणी अभिरक्षक (मानद), संतराम मरावी सरपंच पटुवा और क्षेत्रीय अमला मौजूद रहा। 12 दिनों के अंदर कान्हा नेशनल पार्क में हुई दूसरी बाघ मृत्यु है। इससे पहले, किसली क्षेत्र में दो बाघों के बीच लड़ाई में एक मादा बाघ की मौत हो गई थी। उस मादा बाघ की उम्र लगभग 10-12 साल थी। बाघों के बीच बढ़ते संघर्ष चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। कान्हा ही नहीं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी बाघों की मौत के बढ़ते आंकड़े वन्यजीव विशेषज्ञों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं।

राजधानी के प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम पर बनेंगे द्वार

मुख्यमंत्री बोले-प्रदेश के कई स्थानों की पहचान यहां के शासकों से रही है

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है। प्रदेश के समृद्ध अतीत से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने और हमारी संपन्न सांस्कृतिक धरोहर के प्रकटीकरण के लिए राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों पर सम्राट

विक्रमादित्य और राजा भोज सहित महापुरूषों के नाम पर द्वार बनाए जाएंगे। भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों की पहचान यहां के शासकों से रही है। चक्रवर्ती सम्राट के रूप में शासन करने वाले सम्राट विक्रमादित्य की वीरता, न्याय, त्याग, दानशीलता, पराक्रम, पुरुषार्थ और सुशासन से इतिहास में उन्हें विशेष स्थान प्राप्त हुआ। अद्वितीय शासक रहे राजा भोज ने बड़े तालाब सहित अनेकों रचनाओं का निर्माण कराया, जो आज भी भोपाल सहित प्रदेश के कई भागों में उनकी स्मृतियों को जीवंत करती हैं। महापुरूषों के नाम पर द्वार निर्माण की राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी अपने गौरवशाली अतीत से परिचित होंगे और उन्हें गर्व की की अनुभूति होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए।

शादी-विवाह के बिना ही आलीशान घरों में आई 'बारात'

सुबह-सुबह 50 गाड़ियों का काफिला देख हिला सबका दिमाग

सतना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई घर पर दी दबिश

भोपाल। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। बारातियों के भेष में पहुंची टीम ने 5 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे। हुंडी कारोबार, रिसॉर्ट, फ्लोर मिल, सिविल कॉन्ट्रैक्ट और लोहा-लकड़ी के कारोबार से जुड़े लोगों पर यह कार्रवाई हुई। 50 से ज्यादा गाड़ियों में आयी टीम ने सुबह 6 बजे से छापेमारी शुरू की। इस घटना से पूरे संभाग में हड़कंप मच गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी आयकर छापेमारी बताई जा रही है। आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह सतना शहर में धावा बोला। बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। खास बात यह है कि अधिकारी बारातियों के भेष में पहुंचे थे। इससे किसी को शक नहीं

हुआ। लगभग 50 गाड़ियों का काफिला देखकर लोग हैरान रह गए। लेकिन जब छापेमारी शुरू हुई तो सब समझ गए कि मामला क्या है। इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। छापेमारी जिन कारोबारियों के यहां हुई, उनमें प्रमुख हैं: रामा ग्रुप के रामकुमार और सुरेश कुमार गोयल, सेनानी ग्रुप के सुनील सेनानी, सिविल कॉन्ट्रैक्टर अतुल मल्होत्रा, फ्लोर मिल मालिक संतोष गुप्ता और हुंडी कारोबारी व रिसॉर्ट मालिक सीताराम अग्रवाल उर्फ़ रामू। आयकर विभाग को इनके यहां टैक्स चोरी की आशंका है।

भोपाल, इंदौर और जबलपुर के अफसर शामिल

आयकर विभाग के अधिकारियों ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है लेकिन रीवा संभाग में ये विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इसमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर के अफसर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, रामा ग्रुप के नरेश गोयल को केंद्र में रखकर यह पूरी कार्रवाई हो रही है। नरेश गोयल की सतना के सितपुरा और उत्तराखंड में प्लाईवुड फैक्ट्री हैं जबकि रायपुर में टीएमटी सरिया का प्लांट है। बाकी कारोबारी नरेश गोयल के पार्टनर हैं।

डर के मारे बंद कर लिया दरवाजा

सबसे दिलचस्प वाकया हुंडी कारोबारी और रिसॉर्ट मालिक सीताराम अग्रवाल के यहां हुआ। जब आयकर विभाग की टीम उनके गोशाला चौक स्थित घर पहुंची तो उन्होंने डर के मारे दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन अधिकारी कहां मानने वाले थे। वे सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते घर में घुस गए। इसके बाद उन्होंने अंदर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूरी तैयारी के साथ यह छापेमारी की। उन्होंने 50 गाड़ियों का इंतज़ाम किया था। ताकि सभी टीमें एक साथ अलग-अलग ठिकानों पर पहुंच सकें। और किसी को शक न हो, इसलिए गाड़ियों पर 'बारात' के स्टिकर भी लगाए गए थे। यह देखकर लोग भ्रमित हो गए और किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक आयकर विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया था। सीताराम अग्रवाल के गोशाला चौक स्थित घर पर जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। ऐसे में अफसर सीढ़ी लगाकर छत के सहारे घर में घुसे। रामा ग्रुप टिम्बर और लोहा कारोबार से जुड़ा है। वहीं, सिविल कॉन्ट्रेक्टर अतुल मेहरोत्रा की महरोत्रा बिल्डकॉन कंपनी मास्टर प्लान और इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती है। सेनानी ग्रुप के बिट्स इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल हैं।